बम की धमकी के बाद हैदराबाद जा रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट, सुरक्षित उतारा गया विमान

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

(नाइजीरिया) हथियारबंद ग्रुप ने 303 स्कूली बच्चों और 12 शिक्षकों को किया किडनैप, प्रशासन में मचा हड़कंप

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 324 | रायपुर | सोमवार 24 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

'बहुत जल्द बदलेंगी सीमाएं, भारत को वापस मिलेगा सिंध', राजनाथ सिंह का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सिंध के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद किया।

बता दें, सिंध क्षेत्र 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। वहां रहने वाले ज्यादातर सिंधी हिंदू भारत आ गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि एलके आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंधी आज भी सिंध के भारत से अलग होने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के हिंदुओं के लिए सिंधु नदी हमेशा पवित्र रही है और सिंध के कई मुसलमान भी इसकी पवित्रता को आब-ए-जमजम जितना पवित्र मानते थे।

'सभ्यता से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा'

राजनाथ सिंह ने कहा, ÷आज सिंध भूगोल से भले ही भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति से वह हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा।÷ उन्होंने आगे कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कल सिंध वापस भारत आ जाए।÷

PoK पर भी दिया बयान

रक्षा मंत्री ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) भारत को बिना किसी आक्रामक कदम के मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि क्श्यमें लोग खुद आवाजें उठाने लगे हैं और 'आजादी' की मांग कर रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठी बहस

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत को आगे बढ़कर PoK का हिस्सा वापस लेना चाहिए। इसी संदर्भ में राजनाथ सिंह ने कहा कि हालात खुद इस दिशा में बदल रहे हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से चालू होगा, जो 19 दिसंबर तक

संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी 10 नए विधेयक

नईदिल्ली,एजेंसी

आगामी एक दिसंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने कुल 12 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं. इनमें से 10 नए बिल हैं, जिन्हें इस सत्र में पेश किया जाएगा. इन विधेयकों का उद्देश्य शासन व्यवस्था, शिक्षा, बीमा क्षेत्र, सड़क विकास और कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव लाना है.

सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए बिल-

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025 दिवाला एवं शोधन अक्षमता विधेयक (संशोधन) विधेयक 2025 बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025 मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 निरसन और संशोधन विधेयक 2022 राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025 परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक (एसएमसी), 2025 मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025।

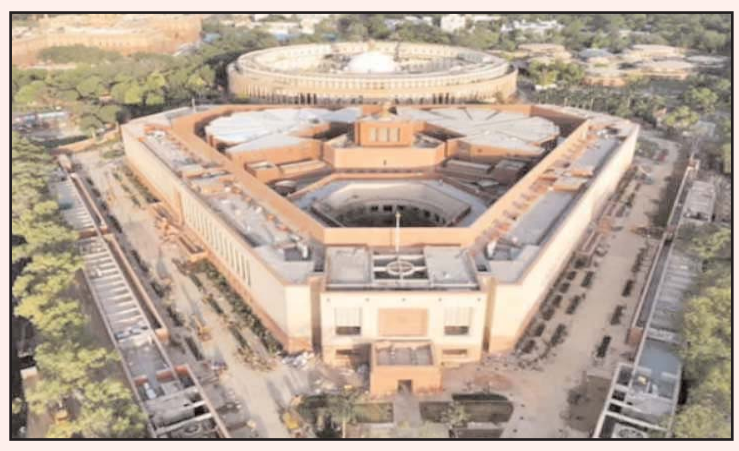

ये अहम बिल होंगे पास

सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने वाला बिल है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और तकनीकी विकास की संभावना बढ़ेगी. इसके अलावा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बिल भी नए सुधारों के साथ लाया जा रहा है, जिससे शिक्षा प्रणाली को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाया जा सकेगा. बीमा सेक्टर, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून, प्रतिभूति बाजार, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे क्षेत्रों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं, ताकि प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाया जा सके.

संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से चालू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1-19 दिसंबर तक संसदीय सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, ÷हम आशा करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक साबित होगा, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।÷

मानसून सत्र में हुआ था हंगामा आगामी शीतकालीन सत्र से पहले संसद का मानसून सत्र देखने को मिला था, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था। इस दौरान संसद में कुल 21 बैठकें हुई थीं। हालांकि, विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों- राज्यसभा और लोकसभा में कोई खास फैसला नहीं देखने को मिला था। मानसून सत्र के दौरान 2 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें 130 से ज्यादा सासंदों ने हिस्सा लिया था। वहीं, लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए थे, जिनमें से 12 बिल पास हुए थे। इसके अलावा राज्यसभा में 15 बिलों को मंजूरी मिली थी।

प्रदूषण पर सरकार का बड़ा एक्शन, डीजल ऑटो पर लगाया कंपलीट बैन

नोएडा ,एजेंसी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सख्त और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नोएडा और गाजियाबाद में डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि यूपी सरकार ने एनसीआर के यूपी क्लस्टर में डीजल वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब इन दो प्रमुख शहरों में डीजल ऑटो सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। यह कार्रवाई प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए गए एक व्यापक एक्शन प्लान का हिस्सा है। प्रशासन ने न केवल नोएडा और गाजियाबाद, बल्कि एनसीआर के अन्य जिलों के लिए भी समयसीमा निर्धारित कर दी है। आदेश के अनुसार, बागपत जिले में भी इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2025 के बाद डीजल ऑटो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

दिल्ली पुलिस और NCB ने जब्त की 262 करोड़ की ड्रग्स, अमित शाह ने की तारीफ

एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (23 नवंबर, 2025) की शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में शाह ने कहा, 'हमारी सरकार अभूतपूर्व गति से ड्रग कार्टेल्स को ध्वस्त कर रही है. जांच एजेंसियां ड्रग्स की जांच में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों नजरिए से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं.' उन्होंने कहा, ''नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की संयुक्त टीम ने 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग्स को जब्त किया है. इसकी कीमत 262 करोड़ रुपये है. यह अभियान कई एजेंसियों के बेहतरीन समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसके लिए हृष्टक्क और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई.''

रामलला की नगरी बनेगी विश्व का आध्यात्मिक केंद्र, सज-धज कर तैयार

-ध्वजारोहण समारोह की लाइव झलक दिखाएंगी 50 से अधिक एलईडी स्क्रीन

-सूचना विभाग ने एलईडी वाल और वैन के जरिए शहर व ग्रामीण को जोड़ा एक मंच से

-सांस्कृतिक विरासत व आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम दिखाएगा अयोध्या

अयोध्या ,

रामलला की नगरी अयोध्या एक बार फिर विश्व पटल पर एक नया अध्याय लिखने जा रही है। 25 नवम्बर को होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह को लेकर शहर में असाधारण उत्साह और व्यापक तैयारी देखने को मिल रही है। इस आयोजन को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और तकनीकी गरिमा को विश्व भर में प्रदर्शित करने वाले महोत्सव के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पूरे शहर को उत्सवमय वातावरण में सजाया जा रहा है। मार्गों को फूलों की लड़ियों, थीम आधारित लाइटिंग और सजावटी तत्वों से चमकाया जा रहा है। ध्वजारोहण के दिन राम मंदिर परिसर में होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि देश-दुनिया का हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन सके। ध्वजारोहण की भव्यता हर कोने में पहुँचे, इसके लिए सूचना विभाग ने बड़े पैमाने पर तकनीकी व्यवस्था खड़ी की है। जिला सूचना अधिकारी संतोष द्विवेदी के अनुसार अयोध्या नगर व तहसील और ब्लॉक स्तरों पर। में 50 से अधिक स्थानों पर एलईडी वाल और एलईडी वैन स्थापित की जा रही हैं। प्रमुख स्थानों में पोस्ट ऑफिस, तुलसी स्मारक भवन, कारसेवकपुरम, टेढ़ी बाजार, रेलवे स्टेशन, सूर्यकुंड, गुप्तारघाट, राम कथा पार्क, मीडिया सेंटर आदि शामिल हैं। बस स्टैंड, सहादतगंज, देवकाली बाईपास, उदया सहित कई अन्य स्थानों पर भी एलईडी वैन तैनात की जाएंगी। इन स्क्रीन के माध्यम से हर नागरिक अपने घर, मोहल्ले या बाज़ार से इस अलौकिक आयोजन को देख सकेगा।

सम्राट चौधरी पर जदयू के नेताओं ने जताया भरोसा, बोले- गृह मंत्री के रूप में नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाएंगे

पटना बिहार में उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने पर राजनीति के बीच जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेताओं ने भरोसा जताया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस के रोडमैप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, सम्राट चौधरी ने बेहद अहम बात की कि वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था के मॉडल को आगे जारी रखेंगे। विभागों के बंटवारे पर राजीव रंजन ने कहा, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसे क्या विभाग दिया जाए। इसी के तहत उन्होंने गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया है।

जी20 के दो सेशन में शामिल हुए मोदी, साझा किया अपना अनुभव

नई दिल्ली

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने न केवल जी20 की बैठक में हिस्सा लिया, बल्कि जी20 के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। पीएम मोदी ने इसकी एक वीडियो भी साझा की है। आज समिट के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने वीडियो साझा कर लिखा, जोहान्सबर्ग में कल जी20 समिट की कार्यवाही अच्छी रही। मैंने दो सेशन में हिस्सा लिया और खास मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दुनिया के कई नेताओं के साथ अच्छी बैठक भी हुई। पीएम मोदी आज जी20 समिट के तीसरे सेशन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े आठ बजे दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद फिर नौ बजे आईबीएसए की बैठक में वह शामिल हुए। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रही इंडिया-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) मीटिंग हुई। बता दें, यह ग्लोबल साउथ में होने वाला लगातार चौथा जी20 समिट है। जी20 के तीसरे सेशन की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। जी20 के तीनों सेशन का थीम इनक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने जी20 एजेंडा पर भारत की सोच दुनिया के सामने रखी।

विदेश | **मिलिट्री स्टैंडऑफके बाद अपने रिश्तों को नॉर्मल करने की प्रक्रिया**

भारत ने खोला चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा

नईदिल्ली, ।

भारत ने दुनियाभर में रहने वाले चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा खोला दिया है। हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

रिपोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चीन के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा खोल दिए गए है। चीनी नागरिक तमाम देशों के भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावासों से आवेदन कर रहे हैं।

इससे पहले भारत ने इस साल जुलाई में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा दोबारा से शुरू किया। हालांकि, तब वे सिर्फ बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास और शंघाई, गुआंगझोउ, हांगकांग स्थित वाणिज्य दूतावासों में आवेदन कर सकते थे। अब दुनियाभर से आवेदन कर सकेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यटन वीजा जारी करने की शुरूआत तब हुई, जब हाल में दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए कई जन-केंद्रित कदमों% पर सहमति व्यक्त की है। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जो पिछले 5 साल से बंद थी। पहली उड़ान 9 नवंबर को शंघाई से नई दिल्ली पहुंची थी, जबकि 26 अक्टूबर को कोलकाता से गुआंगझोउ के बीच इंडिगो की उड़ान रवाना हुई थी।

जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच घातक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। 9 जुलाई, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिससे संबंधों में नरमी आई। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा सुविधा, उड़ान सेवा शुरू हुई और राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव मनाया गया।

एसआईआर के बीच अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़े पैमाने पर भारत से पलायन

कोलकाता एजेंसी।

बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से भारत-बांग्लादेश सीमा पर अभूतपूर्व हलचल देखी जा रही है। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक बड़ी संख्या में अपने देश लौटने लगे हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और राज्य पुलिस दोनों इस अचानक बढ़ी गतिविधि से निपटने में पूरी क्षमता के साथ तैनात हैं, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ो की संख्या मे पकड़े और लौटाये जाने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या सुरक्षा ढांचे पर भारी दबाव बना रही है। उत्तर 24 परगना, माल्दा और दक्षिण बंगाल के अन्य सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ सप्ताहों मे जो परिदृश्य उभरा है, वह पिछले कई वर्षों मे कभी सामने नहीं आया था। बीएसएफ के अनुसार उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट से ही एसआईआर शुरू होने के बाद लगभग 1600 बांग्लादेशी नागरिक वापस लौट चुके हैं। दशकों से भारत में रहकर वोटिंग करते रहे थे घुसपैठिएसीमा की खुली और नक्शा-रहित पगडंडियों से आने-जाने का प्रयास करने वाले इन लोगों मे बड़ी संख्या ऐसे व्यक्तियों की है, जो 10 से भी अधिक वर्ष भारत में रह चुके थे। इनमें से कई लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, कई ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में अपना नाम दर्ज करा लिया और कई ने यहां स्थायी निवास की तरह अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश भी की। जितने लोग पकड़े गए हैं, उनमें से अधिकतर के पास भारत का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कई सामाजिक योजनाओं के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सीमा पार करते समय पकड़ा जाता है, तो उसके इरादे को केवल घर लौटने का प्रयास मान लेना उचित नहीं होता। अधिकारी बताते हैं कि ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमे अपराधी तत्व भी अपराध कर भागने की नीयत से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। कई मामलों मे कट्टरपंथी या संदिग्ध तत्व भी इसी भीड़ की आड़ मे सीमा से निकलने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पकड़े गए व्यक्ति की गहन जांच, पूछताछ, बायोमेट्रिक मिलान और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य है। यदि किसी भी स्तर पर कोई आपराधिक तथ्य सामने आता है तो बीएसएफ उन्हें राज्य पुलिस के हवाले कर देती है। ऐसे लोगों पर भारतीय कानून लागू होता है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पुलिस और न्यायालय संभालते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के हवाले किए जा रहे घुसपैठिएबीएसएफ के दक्षिण बंगाल के प्रवक्ता ने बताया कि जिन व्यक्तियों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता और जो केवल अवैध रूप से भारत मे रह रहे होते हैं, उनके मामले मे बीएसएफ आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) के हवाले करती है। लेकिन यह प्रक्रिया भी सरल नहीं है। बीजीबी द्वारा स्वीकार्यता मिलने तक इन व्यक्तियों को बीएसएफ के हिरासत केंद्रों मे रखा जाता है, जहां भोजन, चिकित्सकीय जांच और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बीएसएफ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस समय प्रतिदिन सीमा से पकड़े जा रहे अवैध प्रवासियों का आंकड़ा अमूमन तीन अंकों में रह रहा है। कुछ रिपोर्टों में प्रतिदिन लगभग 500 जैसे बड़े आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। यह चिंताजनक है। वे बताते हैं कि 100, 150 या इससे अधिक की संख्या मे प्रतिदिन पकड़ की सूचना मिल रही है, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में अभूतपूर्व है।

भारतीय नौसेना में माहे शामिल होने के लिए तैयार

पीआईबी

भारतीय नौसेना 24 नवंबर, 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) को शामिल करेगी ।

पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन द्वारा आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी करेंगे । माहे का जलावतरण स्वदेशी उथले पानी के लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक होगा - आकर्षक, तेज़ और पूरी तरह से भारतीय। 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, माहे-श्रेणी युद्धपोत डिज़ाइन, निर्माण और एकीकरण में भारत की बढ़ती महारत को दर्शाता है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

कलेक्टर दुदावत का तुमकपाल दौरा जर्जर स्कूल बनेगा स्मार्ट स्कूल, ग्रामीणों की समस्याएं होंगी जल्द दूर

दंतेवाड़ा, । कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शुक्रवार को विकासखंड कटेकल्याण के ग्राम पंचायत तुमकपाल पहुंचकर ग्राम वासियों से सीधे संवाद किया और गांव में उपलब्ध सुविधाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, राशन वितरण व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों की हालत, पेयजल उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीणों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का उन्होंने विस्तार से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दुदावत शासकीय प्राथमिक स्कूल की जर्जर स्थिति देखकर गंभीर हुए और तत्काल इसके उन्नयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह स्कूल जल्द ही स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने संबंधित विभाग को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें उन्नत खेती, मिश्रित फसल प्रणाली और जैविक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि कुलथी, रागी जैसी फसलों के

गुणवत्तापूर्ण बीज कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और किसानों की आमदनी में सुधार हो। ग्रामवासियों ने पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, सड़क मरम्मत और वनाधिकार पट्टों से जुड़े मुद्दे भी कलेक्टर के सामने रखे, जिन पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि गांव की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रखा जाएगा और प्रत्येक समस्या का समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर दुदावत ने आंगनवाड़ी में गुणवत्तापूर्ण पोषण की व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए नियमित जांच और बच्चों के स्वास्थ्य मूल्यांकन को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि गांव में स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाए जाएंगे, युवाओं के लिए कौशल विकास गतिविधियां शुरू की जाएंगी और जिन ग्रामीणों को वनाधिकार का लाभ मिलना है, उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। तुमकपाल के इस निरीक्षण दौरे में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय कर्मचारी मौजूद रहे।

बस्तर यूनिटी मार्च 24 को,

0करीतगांव से मालगांव, ईरिकपाल और जगदलपुर में होंगे कार्यक्रम

0 बस्तर सांसद समेत अन्य जनप्रतिनिधि रहेंगे मौजूद।

जगदलपुर, खेल एवं युवा कल्याण, विभाग द्वारा जिला बस्तर में एकता मार्च (यूनिटी मार्च)का आयोजन 24 नवम्बर सुबह 10 बजे से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्च विकासखण्ड बकावंड के ग्राम पंचायत करीतगांव से प्रारंभ हो टाउन क्लब जगदलपुर प्रागण में समाप्त होगी। बस्तर सांसद महेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यूनिटी मार्च कार्यक्रम किया जाएगा। एकता मार्च विकासखण्ड बकावंड के ग्राम पंचायत करीतगांव के मिनी स्टेडियम से प्रारंभ होकर मालगांव पहुंचेगा। मालगांव में मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, इसके उपरांत पदयात्रा ईरिकपाल पहुंचेगा। इसके बाद ईरिकपाल से रवाना होकर जगदलपुर शहर से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर के समीप रूद्र प्रताद देव टाउन क्लब प्रागण में सभा के रूप में समाप्त होगा। प्रशासन द्वारा आयोजन से संबंधित कार्यो हेतु विभिन्न विभागों को दयित्व सौंपा गया है।

बस्तर में भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश की नई टीम तय, पार्टी की रीति नीति से काम करने के निर्देश

जगदलपुर, भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले की नवीन जिला पदाधिकारियों की टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय की सहमति से भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने आज शुक्रवार को भाजपा जिला पदाधिकारियों की घोषणा की। भाजपा बस्तर जिला के नये पदाधिकारियों में जिला महामंत्री का दायित्व रजनीश पाणिग्रही व परीसराम बेसरा को सौंपा गया है। जिला उपाध्यक्ष नरसिंह राव, ललिता बघेल, आर्येन्द्र सिंह आर्य, रामकुमारी यादव, सफीरा साहू एवं लखीधर बघेल बनाये गये हैं। जिला मंत्री के रूप में फूल सिंह सेठिया, सुब्रतो विश्वास, नारायण ठाकुर, खितेश मौर्य, किरण सेन व रैतूराम बघेल बनाये गये हैं। जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप देवांगन और सह कोषाध्यक्ष बिपिन मालवीय को बनाया गया है। कार्यालय मंत्री रोहित त्रिवेदी और सह कार्यालय मंत्री राजपाल कसेर को नियुक्त किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी व सह मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार शुक्ला को बनाया गया है। सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश केजी एवं सह सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश मिश्रा बने हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने नवीन जिला टीम के सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों से पार्टी की रीति नीति पर सतत काम करते हुये संगठन को मज़बूत बनाने की अपेक्षा की है।

बुनाई के रंग, धमतरी के संग थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

धमतरी, जिला प्रशासन धमतरी द्वारा कलेक्टर अभिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में आज बुनाई के रंग, धमतरी के संग थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले की समृद्ध हथकरघा परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ बुनकरों की आय में वृद्धि हेतु एक समन्वित और सुदृढ़ कार्य-ढाँचा विकसित करना था। कार्यक्रम में राज्य हथकरघा विभाग से श्री लालवानी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक प्रशांत चंद्रकार, डिप्टी कलेक्टर मनोज मरकाम, एन.आर.एल.एम. के जिला कार्यक्रम प्रबंधक-अजीविका अनुराग मिश्रा, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के जिला अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के कंसल्टेंट क्षितिज ठाकुर सहित जिले की सभी बुनकर समितियों के प्रतिनिधि, क्रेता एवं विक्रेता उपस्थित रहे। बैठक में धमतरी जिले में हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विभागीय समन्वय, योजनाओं के अभिसरण, बुनकरों की आजीविका वृद्धि तथा हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए जिला स्तरीय ब्रांड निर्माण के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिला साहू संघ की बैठक में शामिल हुए विधायक भोलाराम

खुज्जी। जिला साहू संघ मोहलाङ्कमानपुरङ्कअंबागढ़ चौकी की निर्वाचन संबंधी बैठक आज मोहला में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनप्रिय विधायक माननीय भोलाराम साहू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

बैठक में जिला, तहसील, परिक्षेत्रीय एवं ग्रामीण इकाइयों के पदाधिकारियों ने भारी संख्या में भाग लिया। विधायक साहू ने समाज के सभी पदाधिकारियों एवं निर्वाचन में शामिल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संगठन सचिव पद के प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। विधायक साहू का विशेष संदेश– ÷संगठित समाज ही नशामुक्त समाज बना सकता है÷ अपने उद्बोधन में विधायक भोलाराम साहू ने नशाबंदी और नशा मुक्त समाज पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा–

÷गांवङ्कगांव में नशा उन्मूलन के लिए कड़ी पहल की जरूरत है। साहू समाज हमेशा से जागरूक समाज रहा है, यदि हम संगठित

होकर आगे आएं तो नशामुक्त गांव, नशामुक्त समाज और नशामुक्त जिले का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा किया जा सकता है। बेटियों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए नशाबंदी को सामाजिक अभियान बनाना होगा।÷

उन्होंने समाज को हर गांव में नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाने, युवाओं को सही दिशा देने और परिवारों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराने की अपील की।

बैठक में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित मदनलाल साहू, मोहनलाल साहू, यशवंत साहू, अर्जूनदास साहू, भेषराम सार्वा, दिनेश कुमार साहू, शिवप्रसाद साहू, किशोर कुमार साहू, जागेश्वर दास साहू, भीखम सिंह साहू, गणपत दास साहू, रोहित साहू, योगमाया साहू, प्रमिला साहू, नगीना साहू, लता साहू, उदेराम साहू, गिरीश कुमार साहू, प्रमोद साहू, सुनील साहू, कुलदीप साहू सहित ग्रामीण एवं परिक्षेत्रीय साहू समाज के पदाधिकारी शामिल थे।

झालाटोला प्राथमिक शाला में बाल मेले हर्षोल्लास के साथ मनाया

राजनांदगांव। शासकीय प्राथमिक शाला झालाटोला में मंगलवार को हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया। शाला प्रबंधन समिति, शिक्षकङ्कशिक्षिकाओं और ग्रामवासियों के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस मेले ने बच्चों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, कला और सांस्कृतिक प्रतिभा को एक सुंदर मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में छुरिया विकासखंड के बीआरसी श्री विरेंद्र साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बाल मेले में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडल, पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शन, कला कृतियाँ, शैक्षणिक चार्ट, खाद्य स्टॉल एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए कहा–

÷ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, सृजनशीलता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रमुख माध्यम हैं।÷

78वाँ एनसीसी दिवस : पं. शिवकुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय सुरगी में धूमधाम से आयोजन

लगभग 30 कैडेटस ने रक्तदान कर जागरूकता का दिया संदेश

राजनांदगांव।

पं. शिवकुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सुरगी में 78वाँ एनसीसी दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय एवं 38 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी, राजनांदगांव के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. (श्रीमती) विनम्रता जैन के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अधिष्ठाता महोदया के स्वागत उद्बोधन से हुई, जिसके पश्चात एनसीसी कैडेट्स द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ–गायन, कविता पाठ एवं भाषण का प्रदर्शन किया

गया।

इस अवसर पर एचडीएफसी बैंक एवं बालाजी ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीनियर डिवीजन एवं सीनियर विंग के लगभग 30 कैडेट्स ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाजसेवा का संदेश दिया।

कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं एवं प्रतिभागी कैडेट्स को प्रमाण पत्र एवं आकर्षक उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधिष्ठाता डॉ. जैन ने सभी को एनसीसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं त था छात्रङ्कछात्राओं को एकता, अनुशासन और निःस्वार्थ सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने हेतु प्रेरित किया।

लेफ्टिनेंट डॉ. डी. केश्वर निषाद, एनसीसी अधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

एनसीसी गान एवं राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा

स्पीकर डॉ. रमन सिंह के क्षेत्र में सड़कें बदहाल, वाहनों का चलना दूभर

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर एवं राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। प्रमुख ग्रामीण मार्गों पर बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। लंबे समय से मरम्मत न होने पर ग्रामीणों और किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

इन प्रमुख मार्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब खुटेरी से ठाकुरटोला मार्ग सोमनी से परमालकसा मार्ग बुचीभरदा से कुसमी मार्ग भोथीपार खुर्द से सिंघोला मार्ग सुरगी से मुड़पारङ्कमलपुरी मार्ग उसरीबोड़ से आलीखुटा-रानीतरई मार्ग

रवेली से तोरणकट्टाङ्कमनकी मार्ग इन सभी मार्गों पर गहरे और चौड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें कई जगह चारङ्कचार फीट तक धंसान देखने को मिल रही है।

किसानों को फसल ढोने में भारी दिक्कत इन सड़कों से रोज फसल लानेङ्कले जाने वाले किसानों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है– ट्रैक्टर और चारपहिया वाहन बार-बार गड्ढों में फंस रहे हैं **परिवहन लागत बढ़ रही है दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है** मरीजों और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल

ग्रामीणों का कहना है कि ÷यह सड़कें नहीं बल्कि खतरे का रास्ता बन चुकी हैं।÷

सरकार और विभागों की उदासीनता पर सवाल

स्वच्छता, यातायात एवं अतिक्रमण मुक्ति पर नगर पालिका में अहम बैठक

नपा अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने दिए निर्देश, व्यापारियों से की सहयोग की अपील

कवर्धा,संवाददाता।

शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नालियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाने के साथ-साथ हाईटेक बस स्टैंड में शिफ्टिंग की कार्यवाही को लेकर नगर पालिका परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि कवर्धा नगर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित कवर्धा बनाने में आप सब से सहयोग की अपीक्षा है उन्होनें व्यापारियो सें अनुरोध किया कि कवर्धा शहर को अतिक्रमणमुक्त रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसके लिए प्रशासन और व्यापारियों के संयुक्त प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने सभी प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा नगर के विकास और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए सभी से सहयोग प्रदान करने की अपील की। अतिक्रमण-मुक्त एवं सुगम यातायात व्यवस्था हेतु बैठक नगर

पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बैठक में अतिक्रमण मुक्त शहर व सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की। उन्होनें बताया कि शीतला मंदिर से लेकर ऋषभ देव चौक, ऋषभ देव चौक से लेकर महावीर स्वामी चौक होते गुरूनानक चौक एवं गुरूनानक चोक से लेकर रायपुर नाका चौक तथा गुरूतेगबहादुर चौक मेन मार्केट से होते हुए लोहारा मार्ग विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे मार्केट में लोगों का आवाजाही अधिक रहता है चूंकि उक्त मार्गो में व्यापारियों द्वारा सड़को पर सामान रख दिया जाता है जिसके कारण मार्केट मे आने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसके चलते यातायात व्यवस्था भी ठप्प हो जाता है उन्होनें सभी उपस्थित व्यापारियों से अपील किया गया कि दुकान के बाहर सामान ना रखे ताकि लोगों को परेशानी उठाना ना पड़े। सभी व्यापारियों ने पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। हाईटेक बस स्टैण्ड को लेकर हुई चर्चा नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बताया कि नगरवासियों का 8 वर्ष का लंबा इंतज़ार अब समाप्त होने जा रहा है क्योंकि पुराना बस स्टैण्ड अब नए हाईटेक बस स्टैण्ड में स्थानांतरित किये जाने की तैयार की जा रही है। उन्होनें बताया कि घोठिया रोड सड़क मार्ग का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नालियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने तथा हाईटेक बस स्टैंड में शिफ्टिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा की। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही की सहमति नगर पालिका अध्यक्ष ने चैम्बर ऑफकॉमर्स के सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। इसी तरह नालियों के उपर अतिक्रमण, शहर में गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों के उपर भी शिकंजा कसा जायेगा एवं कार्यालय द्वारा नोटिस भी थमाया जायेगा। चैम्बर ऑफकॉमर्स के सदस्यों ने अध्यक्ष चंद्रवंशी की इस पहल का स्वागत करते हुए नगर विकास में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और व्यवस्थित शहर सभी नागरिकों तथा व्यापारियों की साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए हर स्तर पर सहयोग दिया जाएगा। सभी सदस्यों ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर के लिए प्रशासन एवं व्यापारियों का संयुक्त प्रयास अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए वे पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं। इस बैठक में राजस्व एवं बाजार समिति के सभापति अजय ठाकुर, पार्षद योगेश चंद्रवंशी, संजीव कुर्रे, चैम्बर ऑफकॉमर्स के अध्यक्ष दिनेश जैन, आकाश आहूजा, राकेश दोषी, गौतम लुनिया, अनिल दानी, राजेश गुप्ता, अजय लुनिया, सूचित बोथरा, बल्लूराम सिंह, प्रफुल्ल जैन।

किसान सम्मान निधि पंजीयन शिविर

कलेक्टर द्वारा बीसी सखी तथा जैविक कार्यकर्ताओं की ली गई बैठक

दंतेवाड़ा, । जिला पंचायत के सभागार में आज कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा किसान सम्मान निधि पंजीयन शिविर के संबंध में आवश्यक बैठक ली गई। ज्ञातव्य है कि आगामी 1 दिसंबर से किसान सम्मान निधि पंजीयन शिविर की शुरूआत जिला स्तर पर की जायेगी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना शासन की किसानों के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी और प्राथमिकता वाली योजना है, और जिले के किसानों को इसका अधिकतम लाभ देने के लिए बीसी सखी एवं जैविक कार्यकर्ता की अहम भूमिका रहेगी। इसके तहत किसानों को इस योजना से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी, पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज, शिविर में लाने के लिए सभी बीसी सखी और जैविक कार्यकर्ता शिविर दिवस से पूर्व से ही तैयारी कर लेवे। वर्तमान में जिले में किसान सम्मान निधि के तहत पंजीयन में अपेक्षित प्रगति नहीं है। अतः लक्ष्य अनुरूप अधिक से अधिक से किसानों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास करें। बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि पंचायतों में अटल सुविधा केन्द्र के माध्यम से ग्रामीणों को पेंशन प्रदाय, महतारी वंदन के लाभ तथा कृषक पंजीयन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि उन्हें गावं के समीप ही सभी सुविधा उपलब्ध हो सकें।उल्लेखनीय है कि किसान सम्मान निधि पंजीयन के तहत शिविर आयोजन से 3 दिवस पूर्व सम्बंधित ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा चयनित कृषकों की सूची कोटवार को उपलब्ध कराते हुए शिविर आयोजन की तिथि के बारे में मुनादी कराया जायेगा। इसके अलावा ग्राम के सभी जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषक मित्र, जैविक कार्यकर्ता के साथ आवश्यक बैठक आयोजित कर वंचित हितग्राहियों के नामों का वाचन करते हुये शिविर स्थल पर सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जायेगी।

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान हमारे राष्ट्रीय जीवन का सशक्त प्रतीक – राज्यपाल श्री डेका

राजभवन में मनाया गया 6 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस*

रायपुर, लोकशक्ति। राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज राजभवन में 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान इसी एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त प्रतीक है। राजभवन में रविवार को छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख, और अंडमान निकोबार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि यह पहल केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान नहीं, बल्कि भावनात्मक एकीकरण का माध्यम है।

केन्द्र सरकार के ÷एक भारत-श्रेष्ठ भारत÷ कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते है। इसी कड़ी में आज राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में इन राज्यों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि भाषाओं, वेशभूषा, खान-पान, कला और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हमारी आत्मा एक है। यही विविधता भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है। आज जिन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वे भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और अधिक उजागर करते हैं।

श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण राज्य है। यहां कि संस्कृति रामायण काल की है। यह भगवान श्री राम की कर्म भूमि है। छत्तीसगढ़ में 35 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं जिनकी अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और जीवनशैली है। राज्य की जनजातीय परंपराएं देशभर में विशिष्ट पहचान रखती है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भारत की खनिज राजधानी कहा जाता है साथ ही यह धान का कटोरा भी है। यहां पर्यटन की भी काफी संभावनाएं हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रायपुर 'एजुकेशन हब' बनने की ओर अग्रसर है। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ा कर इस क्षेत्र को शैक्षणिक दृष्टि से और अधिक विकसित किया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का हृदय है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा और इतिहास के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने अंदर समेटे हुए है। धार्मिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से यह देशी-विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। खजुराहो के रहस्यमय मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो अलग-अलग राज्य हैं, लेकिन दोनों राज्यों के निवासियों का खान-पान, भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज कुछ हद तक एक जैसे हैं और वे आपसी स्नेह के अटूट बंधन में बंधे हैं।

श्री डेका ने कहा कि एक 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन भाषा, संस्कृति और विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था। आज केरल अपनी शैक्षणिक उन्नति, स्वास्थ्य सेवाओं, साहित्य, कला, सांस्कृतिक विरासत और सुंदर समुद्री तटों के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल बन चुका है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य सूचकांक और लैंगिक समानता में केरल पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। केरल में 96 प्रतिशत साक्षरता दर है। यहां शिक्षा को सामाजिक अधिकार की तरह माना जाता है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सदाबहार हरियाली के लिए प्रसिद्ध यह राज्य पर्यटकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। हम केरल के प्राचीन इतिहास, लंबे समय से चले आ रहे विदेशी व्यापार संबंधों, विज्ञान और कला की समृद्ध परंपरा पर गर्व कर सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के उच्चतम भाग, और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहां स्थित वैष्णो देवी और अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं। यह प्रदेश बहादुरी, साहस और देश की सीमा सुरक्षा के गौरव का प्रतीक भी है।

श्री डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख का हर दृश्य प्रकृति की अनोखी रचना जैसा प्रतीत होता है। यहां की बौद्ध संस्कृति और हिमालयी जीवनशैली से पूरे देश को शांति और सन्तुलन का संदेश मिलता है। यहां के लोग पर्यावरण के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि अंडमान- निकोबार द्वीप समूह न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं बल्कि 'सेल्यूलर जेल' जैसे ऐतिहासिक स्थल भी यहां है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की पीड़ा और पराक्रम को याद दिलाता है।

राज्यपाल ने कहा कि इन राज्यों की यह विविधता ही भारत की एकता की सबसे बड़ी गारंटी है। यही 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना है, जिसका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक परिचय नहीं, बल्कि भावनात्मक एकीकरण है। जब राज्य एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तो न केवल संस्कृति, बल्कि शिक्षा, व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नए अवसर बनते हैं।

उन्होंने सभी से अपील की कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं। साथ ही उन्होंने लोगों का आव्हान किया कि एक कार्य ऐसा जरूर करें, जिसमें मानवीय सेवा निहित हो।

समारोह में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों की विशेषताओं, परंपरा, संस्कृति पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सभी राज्यों की संस्कृति एवं लोक परंपरा आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के लोक-नृत्य, मध्यप्रदेश के बुंदेलखंडी नृत्य, जम्मू कश्मीर के राउफ सहित केरल के लोक नृत्य गौपति, लद्दाख के जबरो नृत्य एवं अंडमान निकोबार के लोक नृत्यों ने अतिथियों का मन मोह लिया।

विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी, श्री अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं इन सभी राज्यों के युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ सम्मान, रायपुर आवास पर हुआ समारोह

भारतीय ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक आरएन तिवारी ने उन्हें यह सम्मान पत्र सौंपा

रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को आज उनके निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक आरएन तिवारी ने उन्हें यह सम्मान पत्र सौंपा। इस दौरान साहित्य, कला और संस्कृति जगत की अनेक प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं।

88 वर्षीय शुक्ल हिंदी के 12वें लेखक हैं, जिन्हें यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दिया गया है। छत्तीसगढ़ से यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले साहित्यकार हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने साहित्यकार शुक्ल के रचनात्मक कार्यों और हिंदी साहित्य को मिले उनके विशिष्ट योगदान की जमकर प्रशंसा की।

हिंदी साहित्य को दी ऊंचाई

शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य के चुनिंदा कथाकारों और कवियों में से एक हैं , जो अपनी विशिष्ट भाषा, शांत गहनता और अद्भुत कल्पनाशीलता के बल पर साहित्य को नई

ऊंचाई दी है ।

उनकी चर्चित कृतियां – शुक्ल की प्रमुख कृतियों में नौकर की कमीज,'खिलेगा तो देखेंगे' और 'दीवार में खिड़की रहती थी', लगभग जयहिन्द जैसे उपन्यासों और कई उल्लेखनीय कविता संग्रह ,समाज के सूक्ष्म अनुभवों ,साधारण मनुष्यों की दुनिया और जीवन की विसंगतियों को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। उनकी लेखन शैली धीमी रोशनी में चमकते सत्य की माना जाता है है।

अनूठा और सादगी भरा लेखन

उन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके अनूठे और सादगी भरे लेखन के लिए जाना जाता है। वर्ष वर्ष 1979 में नौकर की कमीज नाम से आए उनका उपन्यास पर फिल्मकार मणिकौल ने 1999 में फिल्म बन चुके हैं। यह फिल्म 'केरल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह' में सम्मानित की गई थी। शुक्ल के दूसरे उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है।

चार लेबर कोड लागू होने पर सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा– ये ऐतिहासिक निर्णय

रायपुर,

। केंद्र सरकार ने चार लेबर कोड को लागू कर दिया. पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स के एक पोस्ट के माध्यम से दी। चारों लेबर कोड के लागू होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय देश के उद्योगों, कामगारों और एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके सीएम ने लिखा कि यह स्वतंत्रता के बाद सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम सुधार हैं, जो श्रमिकों को सशक्त बनाते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति देते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इन सुधारों से छत्तीसगढ़ को भी सीधा लाभ मिलेगा. राज्य की 'औद्योगिक विकास नीति 2024-30' में तय किए गए लक्ष्य के अंतर्गत औद्योगिक विकास, नए निवेश, स्स्स्थ विस्तार और रोजगार सृजन इन कोड्स के लागू होने से और अधिक मजबूत होंगेद्ध सरल अनुपालन और पारदर्शी प्रक्रियाएं छत्तीसगढ़ को देश के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में स्थापित करेंगी।

'श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी राहत'

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पोस्ट में आगे लिखा कि लेबर कोड लागू होने से श्रमिक वर्ग को भी बड़ी राहत मिलेगी। न्यूनतम वेतन की प्रभावी गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल, समय पर वेतन भुगतान और सेवा-शर्तों की स्पष्टता, ये सभी लाभ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और उद्योग-श्रमिक संबंधों को स्थिर बनाएंगे। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आपके नेतृत्व में यह ऐतिहासिक सुधार छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण को नई ऊंचाई देंगे।

29 कानूनों के स्थान पर 4 लेबर कोड

भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को 21 नवंबर, 2025 से लागू करने की घोषणा की है। इसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया जा रहा है। श्रम नियमावली को मॉडर्न बनाकर, मजदूरों की भलाई को बढ़ाकर और श्रम इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत, उद्योग-अनुकूल बनाने की नींव रखता है। जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।

चौपाटी को हटाकर एजुकेशन हब विकसित करने की तैयारी, मूणत ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

रायपुर, साइंस कॉलेज मैदान के सामने बनी चौपाटी को अवैध बताते हुए भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि राज्य सरकार इस स्थान को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि भूमि सरकारी होने के बावजूद बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चौपाटी का निर्माण किया गया था। मूणत ने कहा कि दुकानदारों को हटाने के बजाय उनके पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया जारी है, जिससे किसी की आजीविका प्रभावित न हो। मूणत ने आरोप लगाया कि पूर्व भूपेश सरकार के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित यूथ हब और ग्रीन कॉरिडोर को बदलकर चौपाटी बना दी गई। उनका कहना है कि इससे राजनीतिक संरक्षण और व्यावसायीकरण साफदिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस स्थान पर लाइब्रेरी और अध्ययन हेतु शांत वातावरण तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस दुष्प्रचार कर शहरवासियों को भ्रमित कर रही है। विधायक ने कहा कि अवैध चौपाटी का मुद्दा पिछले साढ़े तीन वर्षों से उठाया जा रहा है और भाजपा ने निर्माण के विरोध में धरना और कानूनी प्रक्रिया दोनों का सहारा लिया।

एसआईआर का चक्कर कामकाजी महिला पुरुष एवं रोज कमाने खाने वाले परेशान

0 2003 की मतदाता सूची को आधार मानने के कारण सूची में मृतक मां बाप तथा सगे संबंधियों का काम खोजते हुए लोग हलाकान

0 बीएलओ तथा बीएलए को खोजते खोजते लोग परेशान

रायपुर,

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजधानी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छग के निर्देश पर एसआईआर मतदाता गहन पुनरीक्षण के काम को लेकर कामकाजी महिलाएं पुरुष प्रतिदिन कमाने खाने वाले श्रमिक सहित अन्य लोग परेशान है। यहां पर भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची 2003 को आधार बनाया गया है। इस सूची को ढूंढने में बीएलओ तथा बीएलए दोनों परेशान हो गये है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर का काम शुरू हो गया है। छग 24 हजार मतदान केंद्र है। इसी आधार पर बीएलओ नियुक्त किये गये है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में बीएलए नियुक्त किया है लेकिन मतदाता सूची के कई भाग और वार्ड के विधानसभा का विभाजन परिसीमन के आधार पर हो गया है। जिसके कारण अब सूची में नाम ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता को भी यहां पर ड्यूटी लगाई गई है बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्रक दे रहे हैं। लेकिन इस फार्म में दस पंजीयन के आधार दिये गये है जिसमें आधार कार्ड को प्रमाण नहीं माना गया है।

2003 की मतदाता सूची में नाम खोजना कठिन

प्रदेश में इस समय एसआईआर का काम कठिन हो गया है मतदाताओं के लिए यह सिरदर्द हो गया है वहीं इसके चलते भाजपा और कांग्रेस में सियासी उबाल आ गया है। भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं ने सीईओ से मिलकर डेट बढ़ाने की मांग की है। इधर बीएलए मतदाताओं से पिता का नाम जन्मप्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य दस बिंदुओं की जानकारी मांगते है तो मतदाता और परेशान हो जाता है। गणना पत्रक देने के पश्चात फार्म भी भरना पड़ता है जिसको लेकर दैनिक मजदूर तथा अन्य लोग रोज कमाने खाने वाले लोग परेशान हो गये हैं। इसलिए च्वाइस सेंटर से लेकर पार्षदों एवं विधायकों के निवास में चक्कर काट रहे हैं। इधर राज्य में कांग्रेस ने एक निगरानी समिति बना दी है वहीं भाजपा के द्वारा भी यहां पर विभिन्न समितियां बनाई गई है अब संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारा गया है।

पुरानी मतदाता पर्ची तथा 2009 की भी पर्ची काम नहीं आ रही है। जिसके चलते मतदाता परेशान हो गये है। रायपुर शहर पहले दो विस क्षेत्र में बँटा था अब चार में बंट गया है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यही हालत है परिसीमन में नया क्षेत्र आने के कारण ग्रामीणजन भी परेशान हो रहे हैं। बीएलओ के अनुसार एसआईआर बनाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को परेशानी न हो इसी आधार पर भारत की नागरिकता तय की जाएगी।

रायपुर में सभी संपत्तियों का नया हाई–टेक सर्वे, 60 हजार तक नई संपत्तियां टैक्स दायरे में आने की संभावना

रायपुर,

राजधानी में नगर निगम अब शहर की सभी संपत्तियों का नया, व्यापक और तकनीक आधारित सर्वे शुरू करने जा रहा है। निगम सूत्रों के अनुसार, महीने के अंत तक सर्वे का औपचारिक शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए एक निजी सर्वे कंपनी से अनुबंध की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्क ऑर्डर जारी होते ही टीम घर-घर पहुंचकर संपत्तियों का डेटा जुटाएगी, जिससे अब तक रिकॉर्ड से बाहर संपत्तियों को टैक्स सिस्टम में शामिल किया जा सके। नगर निगम ने पिछली बार वर्ष 2017-18 में विश्व बैंक की सहायता से जीआईएस तकनीक के माध्यम से सर्वे कराया था, जिसमें लगभग 3.52 लाख संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन इसके बाद शहर के तेज विस्तार के चलते नए मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स और प्लॉटिंग

प्रोजेक्ट तेजी से बढ़े। निगम का अनुमान है कि करीब 50 से 60 हजार नई संपत्तियां अभी तक दर्ज नहीं हो पाई हैं। इस बार ड्रोन की जगह रडार आधारित 3डी सर्वे की तकनीक अपनाई जाएगी। इस तकनीक से भवनों की ऊंचाई, मंजिलों की संख्या, संरचना और स्थलाकृति का सटीक त्रि-आयामी नक्शा तैयार होगा। इससे भविष्य में सिवरेज, पेयजल, सड़क और शहरी ढांचा विकास की प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। परियोजना लागत पहले 60 करोड़ रूपए आंकी गई थी, पर नई तकनीक के कारण लगभग 2 करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी। निगम ने 10 कंपनियों से टेक्निकल प्रेजेंटेशन लेकर ड्रोन, रडार और सैटेलाइट सर्वे की तुलना की। 2017-18 के सर्वे में करीब 80 हजार संपत्तियों में माप और श्रेणीकरण संबंधी त्रुटियां मिली थीं, जबकि 1.5 लाख संपत्तियों का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं था। लगभग 40 हजार संपत्तियों में मालिक बदलने के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ था। इस बार दो-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी—पहले रडार सर्वे और फिर निगम टीम द्वारा घर-घर सत्यापन। सत्यापन चरण में संपत्ति स्वामी को फोटो और विवरण सहित नोटिस दिया जाएगा। यदि किसी तरह की त्रुटि मिलती है तो 7 दिनों में दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए अलग सेल भी बनाया जाएगा।

मुख्य बिंदु

रडार सर्वे की अनुमानित लागतः 80-90 करोड़ रुपए

प्रति संपत्ति लागतः लगभग 150 रुपए

नई संपत्तियों का अनुमानः 50,000-60,000

संभावित वार्षिक अतिरिक्त राजस्वः लगभग 100 करोड़ रुपए

इस पहल से नगर निगम को राजस्व में बड़ा इजाफा होने की संभावना है, वहीं शहर का डिजिटल और अद्यतन संपत्ति रिकॉर्ड तैयार होगा।

कलेक्टर ने सीजीपीएससी चयनित अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं कहा – सारे युवा हमारे प्रदेश के गौरव

प्रोजेक्ट अनुभव, नालंदा, तक्षशिला तथा सेन्ट्रल लाइब्रेरी के अभ्यर्थियों को मिली सफलता

रायपुर, । आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित हुए युवाओं से कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने मुलाकात कर मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी व उज्जवल भविष्य की कामना की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अनुभव के तहत आयोजित मॉक इंटरव्यू में भाग लिया था एवं कुछ ने नालंदा, तक्षशिला और सेन्ट्रल लाइब्रेरी में अध्ययन भी किया

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि आज की शाम हम सबके लिए सुखद अनुभव लेकर आई है, जब हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये सभी युवा आज छत्तीसगढ़ का गौरव हैं, जिनमें से कुछ ग्रामीण परिवेश से भी हैं। जल्द ही इनकी पदस्थापना होगी और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। डॉ. सिंह ने कहा कि शासकीय सेवा में आने के बाद आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। आप शासन द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे ही, साथ ही यह अवश्य याद रखें कि जनसेवा सर्वोपरि है। जब आपके समक्ष कोई जरूरतमंद आए, तो उसकी बात संवेदनशीलता से सुनें और उसकी समस्या के निराकरण का प्रयास करें।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा

इस्लामाबाद में हुए बम धमाके में 12 मौतें हुईं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत इसके लिए भारत को दोषी बता दिया। और उतनी ही फुर्ती से इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस पर अपना बयान जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों ने 10 नवंबर को आतंकवाद के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया और उसके कुछ घंटे बाद ही दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार विस्फोट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साजिश का नतीजा बताया है। इस घटना से पूरा भारत हिला हुआ है। मगर अमेरिका ने उस पर प्रतिक्रिया जताने में लगभग 24 घंटे लगा दिए। फिर भारत स्थित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान आया, जिसमें हताहत लोगों के लिए हमदर्दी जताई गई। 11 नवंबर को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक जिला कोर्ट के बाहर हुए बम धमाके में 12 मौतें हुईं।

मजदूर का बहता पसीना ही संगीत

कितनी बार देखा मैंने
उसके माथे से फिसलती एक बूँद
धरती पर गिरकर बज उठती
जैसे कोई पुराना राग भैरवी,
या फिर किसी अधूरे सपने का आलाप।

वह हथौड़ा नहीं चलाता,
वह एक तान छेड़ता
लोहे की थकान से लिपटी हुई तान,
जिसमें मशीनें भी थिरक उठतीं
उसका हथेली पर जमा हुआ छाला
मानो किसी कवि की अधूरी पंक्ति ,
जो जलती है, पर कहती
मैं अभी मजबूत हूँ।

उसके फटे कपड़ों में नहीं,
समय की तहों में छिपा एक ब्रह्मांड
जहाँ भूख, श्रम और स्वप्न
एक ही श्वास में घुलकर गाते
न्याय का अधूरा गीत।
वह चलता
नींद से जूझते सूरज के साथ,
रात की राख में भी खोजता
रोटी का फूल,
और जब धरती के हर कोने में
उसका पसीना रिसता ,
तब संसार में कुछ हरा हो जाता ,
कुछ ध्वनियाँ जीवित हो जातीं ।

उसके कंधों पर रखे ईंटों के बोझ में
इतिहास करवट बदलता,
वह बोलता नहीं,
उसकी चुप्पी में गूंजते
युगों के श्लोक,
कब तक बहाएगा यह मनुष्य
अपने ही श्रम की नदी में रक्त
साहब, आज काम थोड़ा ज्यादा है
और उस मुस्कान में छिपी होती है
धरती की सबसे सच्ची कविता।
क्योंकि
जब वह पसीने की बूँद से
धूल को जीवन देता
तब कहीं पास बैठा ईश्वर
धीरे से कहता–
यही है संगीत, यही सृजन, यही मनुष्य,
और यही रक्त की जगह बेहता पसीना है।

– संजीव ठाकुर,

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन
PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

शराब की लुभावनी पैकेजिंग के खतरे एवं सुप्रीम कोर्ट की चिंता

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने शराब की पैकेजिंग को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की है, वह केवल कानूनी हस्तक्षेप नहीं बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाली चेतावनी है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि शराब को इस तरह आकर्षक और लुभावना बनाकर प्रस्तुत करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ संस्कृति एवं सामाजिक के साथ खिलवाड़ है। चमकीली बोतलें, विदेशी डिजाइन, चटकदार रंग और ग्लैमरस बॉक्स-ये सब रणनीतियां लोगों को, विशेषकर युवाओं को, महिलाओं को शराब की ओर खींचने का साधन बन चुकी हैं। शराब की यह भ्रामक एवं बाजारवादी पैकेजिंग एक गंभीर एवं नया खतरा है। यह प्रवृत्ति केवल बाज़ार का विस्तार नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य, नैतिकता और मानसिक संतुलन पर गहरा हमला है। जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली शराब कम्पनियों की दुराग्रही सोच एवं गुमराह करने वाली पैकिंग एक आपराधिक कृत्य है। जूस पैक जैसे दिखने वाले टेट्रा पैक में बेची जा रही शराब अनेक खतरों को आमंत्रण है।

आज जब देश शराब की वजह से होने वाली बीमारियों, दुर्घटनाओं, हिंसा, पारिवारिक विघटन और मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब शराब को ÷फैशनेबल÷ बनाकर बेचना एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। शराब कंपनियों ने पैकेजिंग को आधुनिकता, प्रतिष्ठा और स्टाइल से जोड़ दिया है, जिससे युवा वर्ग इसे किसी उपलब्धि जैसा मानने लगा है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से यह पैकेजिंग व्यक्ति के मन में यह भ्रम पैदा करती है कि शराब पीना आधुनिकता का प्रतीक है, जबकि वास्तविकता यह है कि शराब हर रूप में शरीर और मन के लिए घातक ज़हर है। शराब के घातक एवं दुष्प्रभाव किसी से छिपे नहीं हैं। यह धीरे-धीरे शरीर को भीतर से खोखला करते हुए नशे की अंधी गलियों में धकेल देती है। लिवर सिरोसिस, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, मानसिक असंतुलन, अवसाद और नींद की गंभीर समस्याएं शराब सेवन की सीधी देन हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले हजारों लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण अपनी जान गंवाते हैं। घरेलू हिंसा, अपराध और परिवारों के टूटने में शराब की भूमिका लंबे समय से प्रमाणित है। ऐसे में शराब को आकर्षक पैकेजिंग में परोसना मानो लोगों को स्वेच्छा से विनाश के रास्ते पर भेजने जैसा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए चिंता जताई है कि शराब की बोतलों की पैकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ता को उसकी वास्तविक हानियों से दूर ले जाए। चेतावनियां अक्सर बोतल के किनारे इस तरह लगाई जाती हैं कि वे दिखती ही नहीं। कंपनियां स्वास्थ्य चेतावनियों को ढककर अपने उत्पाद की सुंदरता को आगे करती हैं। यह न केवल अनैतिक है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की मूल भावना के भी विरुद्ध है। जब सरकार तंबाकू पर बड़ी और भयावह चेतावनियों को अनिवार्य कर चुकी है, तो शराब जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव कई मामलों में उतना ही विनाशकारी है, उसकी पैकेजिंग पर भी समान कठोर नियम लागू होना चाहिए। समाज में शराब की बढ़ती स्वीकृति का बड़ा कारण यह भी है कि शराब उद्योग ने पैकेजिंग को ही आकर्षक विज्ञापन का माध्यम बना दिया है। जहां शराब विज्ञापन पर कानूनी रोक है, वहां कंपनियां रंगीन बोतलों और खूबसूरत बॉक्सों को ही प्रचार का तरीका बना लेती हैं। यह परोक्ष विज्ञापन है, जो कानून की भावना का उल्लंघन करता है और युवाओं को नशे की ओर ले जाता है। ऐसे में सादे, सरल और सामान्य पैकेजिंग की दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है, ताकि शराब किसी ÷लक्ज़री उत्पाद÷ की तरह न दिखे, बल्कि उसका स्वरूप ही लोगों को चेतावनी देने वाला बने।

यह भी चिंताजनक है कि शराब उद्योग का उद्देश्य केवल बिक्री बढ़ाना है, भले ही उससे समाज कितना भी प्रभावित क्यों न हो। वे यह नहीं देखते कि शराब कितने घर बर्बाद कर रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं और कितनी जिंदगियां संकट में हैं। इस मानसिकता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। शराब की ग्लैमरस पैकेजिंग पर रोक लगाने से न केवल उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि समाज में नशामुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण वातावरण भी बनेगा। सरकारों के लिये राजस्व का बड़ा जरिया शराब है, इसलिये सरकारें भी शराब के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी को केवल उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार, समाज और परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। शराब किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसे आकर्षक बनाकर बेचना मानव जीवन के मूल्य को कम करना है। आज आवश्यकता है कि शराब की पैकेजिंग को नियंत्रित किया जाए, उसे सामान्य और गैर-आकर्षक बनाया जाए, स्पष्ट चेतावनियां लिखी जाएं और शराब को समाज में सम्मानजनक स्थान देने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगे। सरकार को भी स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे कानून बनाने चाहिए जो शराब उद्योग की विपणन चालों को सीमित करें।

आज शराब का प्रसार केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन का बड़ा कारण बनता जा रहा है। शराब से जुड़े अपराधों और हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है, विशेषकर महिलाओं के प्रति अत्याचार, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना का बड़ा कारक शराब ही बन रही है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली लगभग आधी हिंसक घटनाओं में शराब प्रमुख भूमिका निभाती है। नशे में धुत्त पुरुष अक्सर पारिवारिक तनाव, गुस्से और असंतुलन के कारण महिलाओं पर अत्याचार कर बैठते हैं, जिससे न केवल उनका आत्मसम्मान टूटता है बल्कि पूरा परिवार भय, असुरक्षा और अपमान के वातावरण में जीने को मजबूर हो जाता है। शराब का यह प्रभाव किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण से शहरी, गरीब से सम्पन्न वर्ग तक फैल चुका है और इसे अनदेखा करना अब समाज के लिए संभव नहीं।

चिंता का विषय यह भी है कि शराब अब केवल बार या नाइट क्लबों तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक अवसरों-शादियों, जन्मदिनों, दफ्तर की पार्टियों, त्योहारों, यहां तक कि छोटे सामाजिक समारोहों में भी परोसी जाने लगी है। शराब को ÷सामाजिकता का हिस्सा÷ और ÷आधुनिकता का प्रतीक÷ बताकर जिस तरह से उसकी पैठ बढ़ाई जा रही है, वह एक खतरनाक सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत है। परिवारों में युवा पीढ़ी अपने बड़ों को शराब का उपभोग करते हुए देखकर इसे सामान्य मानने लगी है, जिससे किशोर अवस्था में ही शराब सेवन की शुरुआत हो जाती है। स्कूल-कॉलेज के छात्र फैशन, दबाव, दोस्तों की नकल और विज्ञापन जैसी पैकेजिंग के प्रभाव में आकर शराब की लत में डूब रहे हैं। यह पीढ़ी मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्तर पर कमजोर होती जा रही है। शराब न केवल उनकी पढ़ाई, कैरियर एवं सोचने-समझने की क्षमता को नष्ट करती है, बल्कि भविष्य के परिवार एवं समाज की नींव तक को हिला देती है। इन बढ़ती चिन्ताओं का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक पुनर्संयम और परिवारों में जिम्मेदार व्यवहार से ही संभव है।

समाज तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम शराब को आकर्षण का नहीं, विनाश का प्रतीक मानें। उसकी पैकेजिंग में चमक-दमक नहीं, चेतावनी झलके। उसका सेवन आधुनिकता नहीं, दुर्बलता समझा जाए। यह चेतना तभी बढ़ेगी जब कानून भी कठोर होंगे और समाज भी सजग। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी इसी दिशा में एक गंभीर कदम है, अब सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि इसे वास्तविक सुधार में बदला जाए।

यह निजी विचार है।

राजकोषीय नीति से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा– जीएसटी 2.0 पर्यटन पुनरुत्थान को गति दे रहा है

–कम टैक्स, अधिक भरोसा और किफायती यात्रा में बढ़ोतरी, ये सभी भारतीयों के अपने देश को जानने–समझने के तरीके को फिर से तय कर रहे हैं

ज्ञान भूषण और डॉ. प्रतीक घोष

भारत में पर्यटन हमेशा घूमने-फिरने से कहीं ज़्यादा रहा है: यह संस्कृतियों के बीच संवाद है, प्रदेशों के बीच एक पुल है और लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन है। फिर भी, दशकों तक, पर्यटन क्षेत्र पर अलग-अलग टैक्स, ज़्यादा लागत और असमान विकास का बोझ रहा। हालाँकि, हाल ही में पेश की गई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पुनर्संरचना इस गाथा को फिर से लिखने में मदद कर रही है।

होटल, परिवहन और सांस्कृतिक वस्तुओं की कम दर के कारण भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विकास बहुत बढ़ावा मिला है। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि इसने आम यात्री को मज़बूत बनाया है, उनकी जेब में ज़्यादा पैसे आए हैं तथा इससे घूमने-फिरने, व्यवसाय और चिकित्सा पर्यटन पहले से कहीं ज़्यादा सस्ते हो गये हैं। सरल टैक्स, मज़बूत यात्रा अर्थव्यवस्था सालों से, यात्रा ऑपरेटर, होटल और परिवहन सुविधा प्रदाता कई करों, जैसे सेवा कर, वैट और लग्ज़री कर के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता था; जो सभी राज्यों में अलग-अलग होता था। 2017 में जीएसटी आने से कुछ स्पष्टता आई, लेकिन 2025 का सुधार और आगे बढ़ गया है, जिसने सरलीकरण को प्रोत्साहन में बदल दिया है। ?7,500 से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना परिवर्तनकारी साबित हो रहा है। जैसा कि एक बड़े अखबार के लेख में बताया गया है, इस कदम से मध्य आय-वर्ग के परिवारों और बजट यात्रियों- जो भारत के घरेलू पर्यटन का आधार हैं- के लिए यात्रा काफी सस्ती हो गयी है। इसके अलावा, यह विदेशी यात्रियों के लिए भी काफी सुगम होगा, क्योंकि यात्रा लागतें अब दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गई हैं। होटल और होमस्टे ज़्यादा बुकिंग, ज़्यादा समय तक रुकने और ज़्यादा स्थानीय खर्च की रिपोर्ट दे रहे हैं। छोटे उद्यमियों और होमस्टे मालिकों के लिए, कम अनुपालन लागत और एक जैसे टैक्स फ्रेमवर्क ने व्यवसाय व्यावहारिकता को बेहतर बनाया है और औपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, जो पैमाने और स्थायित्व की ओर एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव है।

किफायती आवागमन: समावेश का संचालक पर्यटन, परिवहन संपर्क-सुविधा पर फलता-फूलता है। इसीलिए यात्री परिवहन, खासकर 10 से ज़्यादा

सीटों वाली बसों पर जीएसटी में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कटौती, एक और गेम चेंजर है। इससे पता चलता है कि इस कदम ने तीर्थयात्रियों, छात्रों और परिवारों के लिए अंतर-शहरीय और समूह यात्रा को किस प्रकार ज़्यादा आसान बना दिया है। धार्मिक क्षेत्र से लेकर इको-पर्यटन पार्क और ग्रामीण इलाकों में घूमने की जगहों तक, किफायती आवागमन ने यात्रा को आसान बनाया है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को

पुनर्जीवित किया है। एक ऐसे देश में, जहाँ पर्यटन क्षेत्रीय समानता के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, वहाँ बस किराये में हुई हर बचत सशक्तिकरण का एक ज़रिया बन जाती है। सस्ते और स्वच्छ परिवहन विकल्प न सिर्फ़ पहुँच बढ़ाते हैं बल्कि प्राइवेट गाड़ियों के बजाय साझा यात्रा को बढ़ावा देकर भारत के सतत विकास लक्ष्यों में भी योगदान देते हैं।

सांस्कृतिक निवेश: शिल्पकारों को सशक्त बनाना भारत की अपील सिर्फ़ उसके परिदृश्यों या स्मारकों में ही नहीं, बल्कि उसकी जीती-जागती परंपराओं

में भी मौजूद है। इसे मान्यता देते हुए, सरकार ने कला और हस्तशिल्प उत्पादों पर भी जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। हाथ से बुनी हर कांचीपुरम साड़ी, नक्काशीदार चंदन की मूर्ति, या टेराकोटा लैंप एक कहानी कहता है और अब, हर एक शिल्प उत्पाद को सही दामों पर खरीदा जा सकता है। यहां टैक्स कम करना सिर्फ़ एक आर्थिक इशारा नहीं है। यह एक सांस्कृतिक निवेश है। यह उस विविधता को बनाए रखता है, जो भारतीय पर्यटन की आत्मा है, साथ ही यह शिल्पकारों, जिनमें से कई महिलाएं और ग्रामीण उद्यमी हैं, को आजीविका का स्थायी साधन देता है।

संगठित क्षेत्र बनने के प्रति भरोसा

जीएसटी के सबसे लंबे समय तक चलने वाले फायदों में से एक है- स्पष्टता और सही अनुमान। छोटे होटल, यात्रा ऑपरेटर और यात्रा एजेंसियां अब राज्य-विशेष टैक्स को समझने के बजाय एक ही राष्ट्रीय टैक्स फ्रेमवर्क के तहत काम करती हैं। संगठित क्षेत्र बनने के प्रति यह भरोसा ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान प्रणाली के दरवाज़े खोलता है जो उन छोटे व्यवसायों के लिए जीवनरेखा है, जो कभी असंगठित तरीके से चलते थे। यह निवेशकों और उद्यमियों के बीच भरोसा भी बढ़ाता है, जिससे इको-लॉज और हेरिटेज स्टे से लेकर आरोग्य स्थल तक, यात्रा अनुभव में नवाचार होता है।

चिकित्सा पर्यटन: एक स्वस्थ प्रोत्साहन

भारत का उभरता हुआ चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र, जो पहले से ही एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, नए जीएसटी दरों का एक और बड़ा लाभार्थी है। होटल और परिवहन पर कम टैक्स से उन अंतर्राष्ट्रीय मरीज़ों के लिए इलाज पैकेज का खर्च सीधे तौर पर कम हो जाता है जो सस्ती कीमतों पर विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य देख-भाल के लिए भारत आते हैं। इलाज को आराम, पोषण और व्यापक देख-भाल के साथ जोड़कर एकीकृत उपचार अनुभव देने के लिए अस्पताल, आरोग्य केंद्र और आतिथ्य श्रृंखला तेज़ी से मिलकर काम कर रहे हैं। रहने की प्रतिस्पर्धी लागत और आसान यात्रा लॉजिस्टिक्स के साथ, भारत अफ्रीका, मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के उन मरीज़ों के लिए और भी मज़बूत गंतव्य बन रहा है, जो पश्चिमी देशों की तुलना में

पाँचवें हिस्से के खर्च में अच्छी चिकित्सा देख-भाल चाहते हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक प्रभाव

वैश्विक स्तर पर, किफ़ायती खर्च यात्रा के विकल्प तय करता है और हाल तक, भारत थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों से पीछे था, जो कम होटल टैक्स और आसान उप-कर के लिए जाने जाते थे। नई जीएसटी प्रणाली इस अंतर को कम करती है। तर्कसंगत दरों के साथ, भारत अब आयुर्वेद रिट्रीट्स और इको-पर्यटन लॉज से लेकर लग्ज़री हेरिटेज होटलों तक,वैश्विक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विश्व-स्तरीय अनुभव देता है। यह क्षेत्र अभी भारत की जीडीपी में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान देता है और 80 मिलियन से ज़्यादा लोगों को आजीविका देता है। लगातार टैक्स सुधार और अवसंरचना निवेश के साथ, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह योगदान 2030 तक दोगुना हो सकता है, जिससे रोजगार, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के लिए फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएंगे।

स्थानीय विकास, वैश्विक गाथा

आम नागरिकों के लिए, इन सुधारों के फ़ायदे बहुत व्यक्तिगत हैं। एक परिवार, जो कभी ज़्यादा होटल खर्च के कारण छुट्टियां टाल देता था, अब यात्रा को किफायती पाता है। छात्र अध्ययन यात्रा कर सकते हैं, तीर्थयात्री आरामदायक यात्रा कर सकते हैं और दूर-दराज गांवों के कारीगर अपने उत्पाद उन पर्यटकों को बेच सकते हैं, जो उनकी कला की तारीफ़ करते हैं।

सांस्कृतिक रूप से भरोसेमंद और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत की ओर

जीएसटी रेट में बदलाव, सिर्फ़ कागज़ पर लिखी संख्या के बारे में नहीं है। यह सशक्तिकरण के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है कि हर नागरिक को भारत के व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य में यात्रा करने, सीखने और जुड़ने में सक्षम होना चाहिए। पर्यटन को ज़्यादा किफायती, आवागमन को ज़्यादा समावेशी, और उद्यम को ज़्यादा व्यावहारिक बनाकर, ये सुधार अर्थव्यवस्था को लोगों के करीब लाते हैं। ये स्थानीय विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति भारत की तैयारी का भी संकेत देते हैं।

यात्री के लिए, इसका मतलब है ज़्यादा छुट्टियां और बेहतर अनुभव। उद्यमी के लिए, इसका मतलब है ज़्यादा अवसर। भारत के लिए, इसका मतलब है, ऐसी प्रगति जो व्यक्तिगत लगे, जहाँ हर सफ़र एक ज़्यादा जीवंत, समान और भरोसेमंद देश की ओर एक कदम बन जाए।

लेखक: ज्ञान भूषण, (आई ई एस), वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पर्यटन मंत्रालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी), भारत सरकार

संवाद संस्कृति :बच्चों को गलत निर्णय लेने से रोक सकती है

लेखक :प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश

हाल ही में दिल्ली के एक 16 वर्षीय किशोर द्वारा आत्महत्या की दुखद घटना समाज में संवादहीनता की बढ़ती समस्या की ओर गंभीर संकेत देती है। यदि शिक्षक, माता-पिता या परिवार के सदस्य बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और संवाद का खुला वातावरण बनाएं, तो ऐसी अनेक घटनाओं को रोकना संभव है। बाल मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि बच्चों की भावनाओं, दुविधाओं और आंतरिक संघर्षों को समझने के लिए संवाद संस्कृति अत्यंत आवश्यक है।

बच्चे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वे अनेक अच्छे-बुरे अनुभव चाहकर भी अक्सर अभिव्यक्त नहीं कर पाते। भय, संकोच या डांट की आशंका के कारण वे अपने मन की बात छुपा लेते हैं। ऐसे में परिवार और शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें, जहाँ वे बिना डर, झिझक या मूल्यांकन की चिंता के अपनी समस्या, गलती, पीड़ा या अनुभव स्वतंत्र रूप से साझा कर सकें।

ध्यान रखने योग्य बात है कि बच्चे 'उपदेश' से कम और 'पर्यावरण' से अधिक सीखते हैं। यदि घर में संवाद को एक नियमित आदत के रूप में अपनाया जाए, परिवार के सदस्य एक-दूसरे की बात ध्यानपूर्वक सुनें, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से अपना सुख-दुख आगे बढ़कर साझा करने लगते हैं। घर में प्रतिदिन 10ङ्क15 मिनट का ÷फैमिली-टाइम÷ बच्चों में विश्वास, सुरक्षा और आत्मीयता की भावना विकसित करने में अत्यंत प्रभावी हो सकता है।

जब बच्चा कुछ बताता है, तो तुरंत प्रतिक्रियाएँ देना,जैसे ÷तुमने ही किया होगा÷, ÷यह तो गलत है÷, ÷ऐसा क्यों किया?÷-उसके आत्मविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बेहतर है कि बच्चों को धैर्यपूर्वक अपनी बात पूरी करने दें। इससे उनमें निष्पक्ष संवाद, भरोसा और खुलापन बढ़ता है। जो बड़े हैं, मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, उन्हें 'पहले सहानुभूति, फिर सलाह' के सिद्धांत पर चलना चाहिए। सामान्यतः भावनात्मक समर्थन के बाद दिया गया मार्गदर्शन अधिक प्रभावी और स्वीकार्य होता है। इससे बच्चा सच बोलने में सहजता महसूस करता है और परिवार पर उसका भरोसा मजबूत होता है।

बच्चों की निजता का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चा जो भी व्यक्तिगत बात साझा करता है, उसे परिवारजनों, रिश्तेदारों या दोस्तों के बीच चर्चा या मज़ाक का विषय न बनाएं। बच्चे की बातों की गोपनीयता बनाए रखना ही विश्वास की वास्तविक नींव है। जब बच्चा देखता है कि उसकी निजी भावनाएँ सुरक्षित हैं, तो वह आगे भी परिवार के साथ खुलकर संवाद करना सीखता है।

सिर्फ गलतियों पर ध्यान देने से संवाद कमजोर होता है; इसलिए आवश्यक है कि ईमानदारी, साहस, प्रयास, मित्रता, सत्य बोलने जैसी सकारात्मक बातों पर तुरंत प्रशंसा दी जाए। सराहना बच्चे की आत्मछवि को मजबूत बनाती है और भविष्य में भी संवाद के लिए प्रेरित करती है।

आज के डिजिटल युग में संवाद की आवश्यकता और बढ़ गई है, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल गैजेट्स बच्चों के जीवन में गहराई से प्रवेश कर चुके हैं। माता-पिता को सहज शैली में समय-समय पर पूछना चाहिए- ÷क्या ऑनलाइन कुछ उलझन भरा देखा?÷, ÷किसी का बुरा बोलना या मैसेज परेशान करता है क्या?÷, ÷स्कूल में किसी दोस्त या शिक्षक ने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें अच्छा या बुरा लगा हो?÷ ऐसे सौम्य प्रश्न बच्चों को बाहरी दुनिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं।

वस्तुतः संवाद एक ऐसा पुल (ब्रिज) है जो माता-पिता और बच्चों के बीच प्रेम, सुरक्षा, भरोसा और पारदर्शिता को मजबूत करता है। जब हर बच्चा यह विश्वास पूर्वक कह सके-÷मम्मी-पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है÷-तब समझिए कि संवाद संस्कृति ने अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा दी है।

अतः आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं की रोकथाम में परिवार, शिक्षक और मित्रों के बीच विकसित संवाद-संस्कृति सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी और सबसे मानवीय अस्त्र है। **यह निजी विचार है।**

भारत 'पृथ्वी संरक्षण' पर वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने में सक्षम: डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में 26वें 'अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन'को संबोधित किया

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, उभरती प्रौद्योगिकियों और पृथ्वी संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन का आह्वान किया

आधुनिक जटिलताओं से निपटने के लिए अंतरिक्ष, महासागरों और जलवायु पर वैश्विक कानूनों में सुधार करें: डॉ. जितेंद्र सिंह

विश्व बंधु भारत वैश्विक जलवायु और न्यायिक सहयोग का नेतृत्व करने के लिए तैयार: डॉ. जितेंद्र सिंह

पीआईबी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञानराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारत ÷पृथ्वी संरक्षण÷ पर वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने में सक्षम है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, उभरती प्रौद्योगिकियों और पृथ्वी संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन का आह्वान किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने लखनऊ के सीएमएस कानपुर रोड स्थित वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में 26वें 'अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन' में ÷जलवायु न्याय और पृथ्वी संरक्षण: मौजूदा चुनौतियों के लिए कानूनी रूपरेखा÷ विषय पर पैनल चर्चा को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज न्यायाधीश संवैधानिक व्याख्या, वैज्ञानिक समझ और नैतिक जिम्मेदारी के चौराहे पर खड़े हैं, ऐसे में मानवता के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन, महामारियां, साइबर खतरे, महासागरीय क्षरण और तेज़ी से बदलती तकनीकी बाधाएं जैसे ÷अंतर्संबंधित संकटों÷ के दौर से गुज़र रही है। इनमें से कोई भी राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये वैश्विक खतरे समानता, अखंडता और अंतर-पीढ़ीगत न्याय पर आधारित वैश्विक कानूनी प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पहले ही गहरा महासागर मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से लेकर साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और अंतरिक्ष सुधारों में महत्वाकांक्षी पहलों तककई भविष्योन्मुखी मिशनों में खुद को अग्रणी स्थान पर स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये पहल वैश्विक पर्यावरणीय प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विनियमन में सार्थक योगदान देने के लिए भारत की तत्परता को दर्शाती हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह नेनिजता बनाम निगरानी, ??स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वामित्व बनाम डेटा संरक्षण, तथा एआई जनित गलत सूचनाओं की बाढ़ जैसी उभरती कानूनी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से उन क्षेत्रों में कानूनों की व्याख्या करने की अपेक्षा की जाएगी, जो दो दशक पहले तक अकल्पनीय थे, जिनमें अंतरिक्ष मलबा और बाह्य अंतरिक्ष खनन, गहरे समुद्र में संसाधनों का दोहन, सीमा पार जलवायु जवाबदेही तथा साइबर सुरक्षा और एआई नैतिकता का उभरता परिदृश्य शामिल है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत सहित वैश्विक समुदाय से आग्रह किया कि वे मौजूदा कानूनी ढांचों में, विशेष रूप से अंतरिक्ष और महासागरों जैसे क्षेत्रों में, सुधार करें क्योंकि इन क्षेत्रों में पारंपरिक कानून अब आधुनिक जटिलताओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। अंतर-पीढ़ीगत न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि जलवायु, ऊर्जा, अंतरिक्ष या पर्यावरण से संबंधित प्रत्येक कानूनी निर्णय न केवल वर्तमान नागरिकों को, बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा, ÷जलवायु परिवर्तन, महासागरीय क्षरण और अंतरिक्ष मलबा हम सभी के अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे - इनके दुष्परिणाम यहां बैठे युवा लड़के-लड़कियों और आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होंगे।÷

केंद्रीय मंत्री ने भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करने तथा पृथ्वी संरक्षण को कायम रखने के लिए संविधानों, संधियों तथा न्यायालयीन निर्णयों में एक जिम्मेदार व्यक्ति के कर्तव्यों को शामिल करने का आह्वान किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने महासागरों, ध्रुवीय क्षेत्रों, वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी वैश्विक पर्यावरण कानून और साझा ढांचे की वकालत की। उन्होंने सैन्यीकरण, अनियंत्रित संसाधन दोहन और पृथ्वी पर साझा संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए मौजूदा उपायों में सुधार करने की संभावित आवश्यकता का उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह अब चांद पर अवैध खनन देखा जा रहा है, उसी तरह गहरे समुद्र में भी, जहां महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है, ऐसे ही खतरे मौजूद हैं। उन्होंने आगाह किया कि कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना, भविष्य में विवाद और पर्यावरणीय क्षति बढ़ सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर की अदालतें पर्यावरण अधिकारों, नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं और पर्यावरण संरक्षण को तेज़ी से लागू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुकदमेबाजी को जवाबदेही और नीतिगत सुधार के एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, खासकर जब सरकारें जलवायु संरक्षण से जुड़ी कार्रवाई में पिछड़ रही हों।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जलवायु न्यायशास्त्र को आकार देने में न्यायविदों की भूमिका की प्रशंसा की और देशों के बीच मजबूत न्यायिक सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ÷न्यायाधीश अब केवल संविधान के न्यायाधीश नहीं रह सकते, वे आज के युग और समय में मानवता के साझा भविष्य के न्यायाधीश हैं।÷

डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैश्विक महत्व के इस सम्मेलन के आयोजन के लिए सीएमएस निदेशक डॉ. भारती गांधी और सीएमएस अध्यक्ष डॉ. रोजर हेनरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षा, सभ्यतागत मूल्योंऔर विचार नेतृत्व में संस्थान के दीर्घकालिक योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिष्ठित मुख्य न्यायाधीशों, न्यायविदों, शिक्षाविदों और छात्रों की उपस्थिति की सराहना की।

'आईआईटी गुवाहाटी उन्नत समुद्री विनिर्माण का केंद्र बनने के लिए तैयार', श्री सोनोवाल ने कार्यक्रम के उद्घाटन पर कहा

'आईआईटी गुवाहाटी में अंडरवाटर वेल्डिंग कार्यक्रम पूर्वोत्तर में समुद्री क्षेत्र के लिए तैयार नए कुशल कार्यबल का निर्माण करेगा', श्री सोनोवाल ने कहा

पीआईबी

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आईआईटी गुवाहाटी में अंडरवाटर वेल्डिंग, ऑफ्शोर रिपेयर और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3डी प्रिंटिंग) पहल के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर, उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (टीआईएच) में भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) द्वारा समर्थित अंडरवाटर वेल्डिंग प्रमाणन कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सात युवाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए।

मंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी और आईआरएस के बीच सहयोगात्मक प्रयास की सराहना की और आईआईटी गुवाहाटी टीम द्वारा किए गए एक समुद्री प्रोपेलर की 3डी मेटल प्रिंटिंग आधारित मरम्मत का सीधा प्रदर्शन देखा।

इस अवसर पर बोलते हुए, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के÷ मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत की समुद्री क्षमता और कुशल कार्यबल को तेज़ी से मज़बूत किया है, बंदरगाह संपर्क को आधुनिक बनाया है, अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार किया है और नीली अर्थव्यवस्था के विकास को गति दी है। असम और पूर्वोत्तर इस राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।÷ श्री सोनोवाल ने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी में चल रही कौशल विकास और नवाचार पहलों ने पानी के भीतर वेल्डिंग, ऑफ्शोर रिपेयर और अगली पीढ़ी के विनिर्माण में उन्नत क्षमताओं के निर्माण के लिए एक÷ व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी मार्ग÷ खोल दिया है।

श्री सोनोवाल ने कहा, ÷असम में पानी के नीचे की मरम्मत और उन्नत विनिर्माण के लिए एक अग्रणी केंद्र बनने की क्षमता है और आईआईटी गुवाहाटी में टीआईएच इसका भावी केंद्र बनने के लिए तैयार है।÷

भारत ने जॉर्जिया के साथ वस्त्र और रेशम उत्पादन सहयोग मजबूत किया

एजेंसी

केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के सदस्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन आयोग (आईएससी) के महासचिव श्री पी. शिवकुमार के नेतृत्व में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 17-21 नवंबर 2025 के दौरान जॉर्जिया में एक सफल बहु-क्षेत्रीय बैठक संपन्न की जिसका उद्देश्य रेशम उत्पादन, वस्त्र, परिधान और कालीन व्यापार में सहयोग को मजबूत करना था।

प्रतिनिधिमंडल ने 11वें बीएसीएसए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन - कल्टुसेरी 2025 में भाग लिया जहां श्री शिवकुमार ने आईएससी का प्रतिनिधित्व करते हुए उद्घाटन भाषण दिया और पारंपरिक रेशम ज्ञान में भारत के नेतृत्व और रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योगों में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताया। उन्होंने ÷द क्रॉनिकल्स ऑफ वाइल्ड सिल्क÷ शीर्षक से एक तकनीकी शोधपत्र भी प्रस्तुत किया।

सीएसबी के निदेशक (तकनीकी) डॉ. एस. मंथिरा मूर्ति ने भारत के लिए उत्पादक

बाइवोल्टाइन रेशमकीट संकर विकसित करने में भारत-बुल्गेरिया सहयोग पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

इस यात्रा के दौरान, सीएसबी ने अपने अभिनव ÷5-इन-1 सिल्क स्टॉल÷ का प्रदर्शन किया, जो शहतूत, ओक तसर, उष्णकटिबंधीय तसर, मूगा और एरी रेशमों का एक उत्कृष्ट उत्पाद है। सदस्य सचिव की पहल पर तैयार किए गए इस उत्पाद को भारत की समृद्ध रेशम विरासत का एक अनूठा प्रतिनिधित्व बताया गया जिसकी बाज़ार में प्रबल संभावनाएं हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालयों, रेशम उत्पादन प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, वस?त्र कंपनियों, परिधान निर्माताओं, कालीन व्यापारियों और जॉर्जियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) सहित प्रमुख जॉर्जियाई संस्थानों के साथ बातचीत की। इन वार्ताओं में द्विपक्षीय वस?त्र व्यापार को बढ़ाने, उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने और रेशम उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान की संभावनाओं पर ज़ोर दिया गया।

जॉर्जिया सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने, बाजार पहुंच में सुधार करने तथा वस्त्र, परिधान, कालीन और मूल्यवर्धित रेशम उत्पादों में व्यापार का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य परिणाम

रेशम उत्पादन अनुसंधान, वस्त्र एवं परिधान व्यापार में भारत-जॉर्जिया सहयोग को मजबूत किया गया।

5-इन-1 सिल्क स्टॉल, एक संभावित प्रमुख उत्पाद के माध्यम से भारत के नवाचार को प्रदर्शित किया गया।

कालीनों और उच्च मूल्य वाले वस्त्रों सहित व्यापार विविधीकरण के लिए नए रास्ते की पहचान की गई।

संस्थागत साझेदारी और तकनीकी सहयोग के लिए मार्ग बनाए गए।

बीएसीएसए अंतर्राष्ट्रीय मंच में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत की वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ किया।

यह यात्रा भारत की वस्त्र कूटनीति को आगे बढ़ाने और रेशम एवं वस्त्र क्षेत्रों के विकास के लिए सीमा पार साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

भारत ने यूएनएफसीसीसी सीओपी30 के प्रमुख परिणामों का स्वागत किया

भारत ने जलवायु वित्त के मुद्दे को सामने लाने में सीओपी प्रेसीडेंसी के प्रयासों की सराहना की; उम्मीद जताई कि रियो में 33 वर्ष पहले किए गए वादे पूरे होंगे

भारत ने आगाह किया कि समस्या पैदा करने में सबसे कम जिम्मेदार रहने वालों पर जलवायु परिवर्तन के शमन का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए

पीआईबी। भारत ने 22.11.2025 को ब्राजील के बेलेम में यूएनएफसीसीसी सीओपी30 के समापन पूर्ण सत्र में दिए गए उच्चस्तरीय वक्तव्य में सीओपी30 प्रेसीडेंसी के समावेशी नेतृत्व के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया और सम्मेलन में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत किया।

वक्तव्य में सीओपी अध्यक्ष के नेतृत्व के लिए भारत की ओर से आभार व्यक्त किया गया, जो समावेशिता, संतुलन एवं मुतिराओ की ब्राजीली भावना पर आधारित रहा तथा जिसने सीओपी30 का ईमानदारी से मार्गदर्शन किया।

वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (जीजीए) के अंतर्गत हुई प्रगति का स्वागत करते हुए, भारत ने निर्णय के समता वाले आयाम को रेखांकित किया तथा कहा कि यह विकासशील देशों में अनुकूलन की अत्यधिक आवश्यकता की मान्यता को दर्शाता है। भारत के संबोधन का एक प्रमुख तत्व जलवायु वित्त प्रदान करने हेतु विकसित देशों के दीर्घकालिक दायित्वों पर जोर देना था। वक्तव्य में अनुच्छेद 9.1 पर लंबे समय से बकाया ध्यान केन्द्रित करने की दिशा में यात्रा शुरू करने में भारत का समर्थन करने हेतु प्रेसीडेंसी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई। इसमें कहा गया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना से पूरी उम्मीद है कि 33 वर्ष पहले रियो में किए गए वादे अब बेलेम में उठाए गए शुरुआती कदमों के कारण पूरे होंगे। भारत ने सीओपी30 के प्रमुख परिणामों पर संतोष व्यक्त किया, जिनमें सबसे प्रमुख न्यायसंगत बदलाव तंत्र की स्थापना थी। वक्तव्य में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया और उम्मीद जताई गई कि इससे वैश्विक और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर समता तथा जलवायु न्याय को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। भारत ने एकतरफा व्यापार-प्रतिबंधात्मक जलवायु उपायों पर चर्चा के लिए मौका प्रदान करने के लिए प्रेसीडेंसी का आभार व्यक्त किया। ये उपाय सभी विकासशील देशों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं और कन्वेंशन तथा पेरिस समझौते में निहित समता एवं सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया गया कि इन मुद्दों को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसमें आगे कहा गया कि विभिन्न पक्षों ने इस प्रवृत्ति को उलटने की शुरुआत कर दी है। जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए, वक्तव्य में इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के शमन का भार उन लोगों के कंधों पर न डाला जाए जो इस समस्या के लिए सबसे कम जिम्मेदार रहे हैं। कमजोर आबादी, जिनमें से अधिकांश ग्लोबल साउथ में बसी हैं, को और अधिक वैश्विक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से खुद को बचा सकें।

भारत ने विज्ञान-आधारित और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। यह कहा गया कि भारत एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जो नियम-आधारित व न्यायसंगत हो और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करती हो। इसके अलावा, यह राष्ट्र यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जलवायु संबंधी आकांक्षाएं समावेशी, न्यायसंगत और न्यायसंगत हों। अंत में, वक्तव्य में आगे की राह में ब्राजील और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति भारत के समर्थन और आभार की पुष्टि की गई। इसमें सभी पक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया कि बेलेम से शुरू होने वाला मार्ग निष्पक्षता, एकजुटता और सभी के लिए साझा समृद्धि से परिभाषित भविष्य की ओर ले जाए।

विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के तहत विकास को गति देने के लिए केंद्र और जम्मू-कश्मीर की सरकारें साथ आईं

पीआईबी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चूना-पत्थर खनिज की पहली नीलामी औपचारिक रूप से 24 नवंबर, 2025 को जम्मू में शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी करेंगे तथा इसमें जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जो केंद्र-राज्य की मजबूत साझेदारी एवं क्षेत्र के लिए इस पहल के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि 2015 में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत शुरू किए गए खनन सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इन सुधारों के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में होने वाला पहली खनन ब्लॉक नीलामी भी है, जो खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है।

संयुक्त आर्थिक क्षेत्र- ईईजेड की निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना का युद्धपोत 'सावित्री' सेशेल्स के दौरे पर

पीआईबी

भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) आईएनएस सावित्री हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा हुआ है। इसके आगमन पर सेशेल्स तटरक्षक बल के कर्मियों ने पोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह पहल दोनों देशों के बीच गहरे पारस्परिक सम्मान, मजबूत रक्षा सहयोग और सुदृढ़ होते द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को दर्शाती है।

पोर्ट कॉल के दौरान जहाज ने सेशेल्स तटरक्षक बल को महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स सौंपे, जिससे साझा समुद्री क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपने साझेदार देशों की परिचालन क्षमता एवं तत्परता बढ़ाने के प्रति भारत की अटूट वचनबद्धता एक बार फिर स्पष्ट हुई।

आईएनएस सावित्री ने अपने बंदरगाह प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिनमें कार्यात्मक बातचीत, विषय-वस्तु विशेषज्ञों के साथ तकनीकी आदान-प्रदान और सेशेल्स तटरक्षक बल के साथ सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना शामिल था। इसके अलावा, जहाज को आगंतुकों के लिए भी खोला गया, जहां उन्हें भारतीय नौसेना की उन्नत परिचालन क्षमताओं और समृद्ध समुद्री परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिला। आईएनएस सावित्री सेशेल्स तटरक्षक बल के साथ मिलकर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की संयुक्त निगरानी करेगा। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य सेशेल्स के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा, सतर्कता एवं स्थितिजन्य जागरूकता को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। हिंद महासागर क्षेत्र में आईएनएस सावित्री की यह तैनाती भारत के 'क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति' (महासागर) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार व प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में स्थापित करती है।

लोकशक्ति। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी वीर शिवाजी वार्ड खमतराई में एक सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित होने पर कांग्रेस साथी एवं मित्र द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन करते हुए...

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

यहां का भंडारा देखकर जगन्नाथ पुरी की याद आ जाती है –स्वामी मधुसूदनाचार्य जी

जांजगीर चांपा /

यह पहला तीर्थ है जहां बंदर नहीं है, वृंदावन के बंदर चश्मा उतार के ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, अयोध्या के बंदर कुछ शांत और सीधे हैं ।अयोध्या में हमारे साथ बंदर नहीं रहते! हम बंदरों के साथ में रहते हैं। यह बातें अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज ने शिवरीनारायण मठ महोत्सव में स्रोताओं के समक्ष उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि *नदी में डुबकी लगाने के लिए दो वस्त्र होना जरूरी है जब घर में स्नान करते हो तो भी दो वस्त्र होना चाहिए। नहाये हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे यथावत रखने चाहिए करण कि निचोड़ने से जो जल निकलता है उसे पीतर देवता प्राप्त करते हैं।

माताओं को नदी स्नान के समय तीन वस्त्र धारण करना चाहिए। *बेटा यदि अच्छा हो तो एक कुल को पवित्र करता है यदि बेटी अच्छी मिले तो दो कुल पवित्र हो जाते हैं। *हमारा कार्य ही गुरु है इस संसार में कर्म की प्रधानता है। भगवान के चरित्र का गान करते हुए, स्मरण करते हुए, भोजन बनाते हैं तो वह भोजन अमृत बन जाती है। आहार शुद्ध होने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। यहां के भंडारा को देखकर जगन्नाथ पुरी की याद आ जाती है वास्तव में यह जगन्नाथ पुरी ही है। भगवान भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता! वे तभी पकड़ में आते हैं जब स्वयं पकड़वाना चाहें सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होई जाई।। शिवरीनारायण मठ महोत्सव में सप्तम दिवस दोपहर में लोगों की भारी भीड़ थी।

दो त्रिवेणी का अद्भुत संगम यहां देखने को मिल रहा है – कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, अरैल घाट, नैनी के फलाहारी आश्रम के महन्त अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रामरतन दास जी महाराज का आगमन अपने अनुचर राजाराम दास जी महाराज के साथ हुआ, यह देखकर आचार्य जी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में दो त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को प्राप्त हो रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित अति विशिष्ट लोग

शिवरीनारायण मठ महोत्सव में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश जी, फिंगेश्वर राजघराने के राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह, आरएसएस के छत्तीसगढ़ प्रभारी टोप लाल वर्मा, पी आई एल चांपा के कारखाना प्रबंधक पारीख साहब तथा पंडित दिनेश शर्मा ,राघवेंद्र प्रताप सिंह, विजय पाली, रमेश यदु, रामकृष्ण पाली, चंद्रकांत यदु, मनोज मित्तल, पुरुषोत्तम शर्मा, शशि भूषण सोनी, विवेका गोपाल, बृजेश केसरवानी, हेमंत दुबे, सुबोध शुक्ला, निरंजन लाल अग्रवाल, वीरेंद्र तिवारी,पूर्णेन्द्र तिवारी, कमलेश सिंह, हर प्रसाद साहू, प्रमोद सिंह, रमेश पैग्वार, मदन तिवारी, पवन चतुर्वेदी, बजरंग शर्मा, देव कुमार पांडे, राजेश छत्री, हरीश राठौर,कुणाल गुप्ता, सहित अनेक गणमान्य नगरीकरण सम्मिलित हुए।

सीताराम विवाह महोत्सव 25 को

श्री शिवरीनारायण मठ में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तद्नुसार 25 नवंबर को सुबह श्रीमद् भागवत कथा अनवरत चलेगी, शाम को सीताराम विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।

अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री के आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने पकड़ा

जांजगीर चांपा / अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री के आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने पकड़ा है । ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय

आईपीएस के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप* के मार्ग दर्शन में थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर आरोपी बुधराम निवासी सेमरा के कब्जे से 7 लीटर 350 एम एल अवैध कच्ची महुआ कीमती 1450 रुपए को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कमलेश शेन्डे थाना प्रभारी नवागढ़, स उ नि भुवनेश्वर राठौर, आरक्षक देवराज लसार, श्याम कुमार शांते, हेमंत साहू एवम थाना स्टाफका योगदान रहा।

लायंस स्कूल चांपा में हुआ हेल्थ एंड वैलनेस प्रोग्राम

जांजगीर चांपा / लायंस स्कूल चांपा में शनिवार को हेल्थ एंड वैलनेस प्रोग्राम का आयोजन हुआ जिसमें स्कूल के कक्षा 7वीं से 11वीं के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रोग्राम में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित प्राचार्या अजीता वी. के. भी शामिल हुई। प्रोग्राम में वैलनेस कोच के रूप में श्री योगेश देवांगन ने बच्चों को मेंटल हेल्थ एंड केयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्री योगेश ने स्मार्ट स्क्रीन पर बच्चों को मानसिक बीमारी के लक्षण एवं कारणों सहित इसे पहचानने एवं इससे बाहर निकलने के तरीके भी बताएं। बच्चों के उत्साहपूर्ण भागीदारी ने प्रोग्राम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सिरमिना में अवैध भंडारित 20 क्विंटल धान पर हुई जब्ती की कार्यवाही

कोरबा छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप धान उपार्जन केंद्रों में अवैध धान के आवक पर रोक लगाने कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किया का रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समितियों का निरीक्षण करविक्रय हेतु आने वाले धान की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही गोदाम, दुकानों का जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान पर भी जब्ती कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड के ग्राम सिरमिना में नायब तहसीलदार श्री सुमन मानिकपुरी, सहायक खाद्य अधिकारी सरोज उरेती, मंडी सब-इंस्पेक्टर आकाश भारद्वाज एवं दिनेश कुमार के संयुक्त टीम द्वारा संतोष जायसवाल के घर से अवैध भंडारित 20 क्विंटल (50 बोरी) धान जब्त किया गया है। साथ ही आगे की कार्यवाही की जा रही है। जिससे इस धान का समिति में पंजीकृत किसान के खाते से विक्रय ना हो पाए एवं पंजीकृत किसान अपने वास्तविक उपज को केंद्र में विक्रय कर सके।

धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वालों को डराने वाले दो आरोपी चढ़े चांपा पुलिस के हत्थे

जांजगीर चांपा /धारदार हथियार लहराकर आने जाने वालों को डराने के दो आरोपी चांपा पुलिस के हत्थे चढ़ा है । पकड़े गए आरोपीयों में लक्ष्मीप्रसाद पिता पवन भारद्वाज अंबेडकर चौक जगदल्ला चांपा , मंगल सिंह पिता वीर सिंह टंडन छुहिया तालाब जगदल्ला चांपा शामिल है। ज्ञात हो कि जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के द्वारा त्योहार के मद्देनजर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे । इसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, एसडीओपी चापा यदुमणी सिदार के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में थाना चाम्पा से पुलिस टीम थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग हेतु रवाना किया गया था । पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर सूचना पर गौरव पथ रोड के अलग-अलग स्थान से 2 आरोपियों को पकड़ा गया जिनके कब्जे से 2 नग धारदार हथियार जप्त किया गया । दोनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक आर्म्स एक्ट की कार्यवाही किया गया तथा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी चापा, उपनिरीक्षक दादूरईया ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक बाबूलाल दिवाकर, आरक्षक मुद्रीका दुबे, जय उराव, वीरेश सिंह, शंकर राजपूत, भूपेंद्र गोस्वामी का विशेष योगदान रहा ।

कात्रेनगर चांपा में यति यतनलाल सम्मान स्मृति समारोह हुआ भव्य आयोजन

जांजगीर चांपा।

भारतीय कुष्ठ निवारक संघ गौशाला, कात्रेनगर चांपा द्वारा शनिवार 22 नवम्बर 2025 को ÷यति यतनलाल सम्मान ङ्क 2025÷ की प्राप्ति के उपलक्ष्य में एक गरिमामयी स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। संस्था को यह राज्य अलंकरण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अहिंसा एवं गौसंरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नवम्बर माह में नया रायपुर में आयोजित रजत महोत्सव समापन समारोह में महामहिम उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन जी के करकमलों से प्राप्त हुआ था।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री विशेषर सिंह पटेल जी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में गौमाता केवल आस्था का नहीं बल्कि सतत जीवन और स्वावलंबन का भी आधार है। उन्होंने संस्था द्वारा निःस्वार्थ भाव से किए जा रहे निरंतर कार्यों की सराहना की और इसे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे भागवताचार्य श्री राजेंद्र शर्मा जी (टेमर, शक्ति) ने अपने उद्बोधन में गौसेवा को धर्म, संस्कृति व मानवता की मूल धुरी बताते हुए, समाज को इस दिशा में संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जहां गौसंरक्षण होता है, वहीं सद्भाव और अहिंसा का वास होता है।

समारोह के मंच पर श्री सुधीर देव जी, वरिष्ठ प्रचारक एवं सचिव, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ; श्री लक्ष्मीनारायण सोनी जी, अध्यक्ष; तथा श्री लोमसराम जी, प्रचारक; सम्माननीय रूप से उपस्थित रहे। इन्होंने संघ की प्रेरणाओं, लक्ष्य एवं भविष्य की योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की।

कार्यक्रम में प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियाँ विशेष तौर पर शामिल हुईं। इनमें श्री अंबेश जांगड़े, जिला भाजपा अध्यक्ष जांजगीर-चांपा व पूर्व विधायक (पामगढ़), श्री चुन्नीलाल साहू, पूर्व विधायक (अकलतरा), श्री गुलाब सिंह चंदेल, श्री रवि पांडेय, श्रीमती सत्यलता मीरी, अध्यक्ष जिला पंचायत जांजगीर-चांपा, श्री गगन जयपुरिया, उपाध्यक्ष जिला पंचायत और सुश्री आशा साव, जिला पंचायत सदस्य सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। कार्यक्रम में अमित गौरहा, गणेश राम साहू, प्रभा सिंह, अनुराधा शुक्ला, प्रतिमा पाटले, ममता राठौर, दिनेश सिंह चंदेल, मुरारी राठौर, शिव जायसवाल, पुरंदर कश्यप, रामकुमार श्रीवास, श्रीमती लालिमा जायसवाल, जितेंद्र साहू, लोकेश साहू, बुद्धेशर केशरवानी, गोबिंद मिश्रा, अमित सराफ़ लक्षणदास मानिकपुरी सहित अनेक सम्मानित व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

कार्यक्रम की शुरुआत गौमाता पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुई। इसके पश्चात संस्था की अब तक की मेहनत, गौसंरक्षण कार्यों, पशु चिकित्सा सेवाओं एवं समाज में किए गए पुनर्वास प्रयासों का संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण किया गया। सेवाभावी कार्यकर्ताओं को साल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मान व्यक्त किया गया।

समारोह का संचालन श्री घनश्याम तिवारी ने कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया। अंत में संघ द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। समारोह के सफल आयोजन के साथ ही उपस्थित जनसमुदाय ने संगठन के प्रति गर्व व्यक्त करते हुए, गौसेवा में निरंतर सहयोग और सक्रिय सहभागिता की प्रतिबद्धता दोहराई।

एसआईआर छिन लेगा मताधिकार ...!

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के 20 दिन पूरे

संवाददाता । जांजगीर-चांपा।

तस्वीर में नजर आ रहा यह घर ना ही पाकिस्तान में स्थित है और ना ही इस घर में विदेशी घुसपैठिए रहते हैं, यह घर कोई आजकल का बना भी नहीं है, और ना ही दूरस्थ अंचलों में ऐसी जगह बना है जहां तक पंहुचना नामुमकिन हो, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में वार्ड नं. 08 में नहरिया बाबा मुख्य मार्ग में नहर किनारे यह घर स्थित है जिसमें जिले के वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह क्षत्री अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इस घर में अब तक कोई बीएलओ नहीं पंहुचा जबकि एसआईआर प्रारंभ होने से पहले कलेक्टोरेट में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कलेक्टर ने कहा था कि एसआईआर के एक माह में बंद घरों में भी तीन बार बीएलओ पंहुचेंगे। यह स्थिति तब है जब पूरा मामला पहले ही कलेक्टर के संज्ञान में लाया जा चुका है।

04 नवंबर 2025 से प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रारंभ होने से ठीक पहले कलेक्टोरेट जांजगीर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने एसआईआर के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला था। उक्त प्रेस कांफ्रेंस में जब बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पत्रकारों की ओर से बताया गया कि बीएलओ घर घर नहीं जाते बल्कि एक ही स्थान पर बैठकर कार्य को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से ही मतदाता सूची में त्रुटियां रह जाती है, तब कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया था कि 04 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 के बीच जिले के हर घर में बीएलओ घर घर पंहुचेंगे, कोई घर यदि बंद भी पाया जाता है तब भी बीएलओ तीन बार उस घर में जाएंगे। वहीं जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 8 में शिव मंदिर के पास, नहर किनारे, नहरिया बाबा मुख्य मार्ग में स्थित वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह क्षत्री के घर में एसआईआर प्रारंभ होने के 15 दिवस के

दावा : 04 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 के बीच बंद घरों में भी तीन बार पंहुचेंगे बीएलओ

हकीकत : कलेक्टर के संज्ञान में होने के बाद भी जिला मुख्यालय के नहरिया बाबा मुख्य मार्ग स्थित इस घर में एक बार भी नहीं पंहुचे बीएलओ

भीतर भी जब कोई बीएलओ नहीं पंहुचे तब उन्होंने 19 नवंबर 2025 की सुबह 10.17 बजे मैसेज के माध्यम से इसकी जानकारी जांजगीर-चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे को दी जिसके थोड़ी देर बाद ही सुबह 11.38 बजे तहसील आफिस जांजगीर के कर्मचारी उज्जवल तिवारी ने फोन कर उनका इपीक नंबर लिया वहीं एसआईआर प्रारंभ हुए 20 दिन हो जाने के बाद भी अब तक उक्त निवास पर आज तक बीएलओ अथवा निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं पंहुचा है।

उक्त प्रेस कांफ्रेंस में कलेक्टर की ओर से जानकारी दी गई की एसआईआर 2003 के मतदाता सूची को आधार मानकर की जा रही है। प्रेस कांफ्रेंस में ही जब उनसे पूछा गया कि 2003 में कोई मतदाता किसी अन्य वार्ड का निवासी हो और अभी किसी अन्य वार्ड का, अथवा मतदाता सूची में मतदाता का नाम किसी अन्य वार्ड में हो और वर्तमान मे निवास किसी अन्य वार्ड में हो, तब क्या होगा, इस पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया था कि ऐसी स्थिति में मतदाता शिफ्टेड में आएगा और वर्तमान में मतदाता जिस पते पर रहता है वहां जब बीएलओ पंहुचेंगे तो उसे फार्म 6 और फार्म 7 भरना होगा, इससे अच्छा वह फार्म 8 भर ले जिससे कि जैसे ही उसका नाम इस वार्ड में दर्ज होगा, पुराने वार्ड अथवा पुराने स्थान की मतदाता सूची से उसका नाम आटोमेटिक डिलिट हो जाएगा।

अंतिम चुनाव तक वोट दिया, फिर कब कटा नाम ?

वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह क्षत्री द्वारा जब 19 नवंबर को कलेक्टर जन्मेजय महोबे को मैसेज के माध्यम से जानकारी दी गई कि वह पिछले 15 वर्षों से (वर्तमान में भी) अपने परिवार के साथ जिस घर में रह रहे हैं वह जांजगीर में नहरिया बाबा मुख्य मार्ग में नहर किनारे, वार्ड नंबर 8 में शिव मंदिर के पास मौजूद है जहां आज तक कोई बीएलओ नहीं पंहुचा है जिसकी वजह से उनका नाम अभी भी वार्ड नं. 16 के मतदाता सूची में मौजूद है। उनका संयुक्त परिवार वाला घर है, जिसमें हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहते हैं, लेकिन एसआईआर के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बीएलओ नहीं पंहुचा, उसके थोड़ी देर बाद ही तहसील कार्यालय जांजगीर से उज्जवल तिवारी का फोन आया जिसने उनके वार्ड नंबर 16 स्थित पुराने मकान की जानकारी ली कि वो वार्ड नंबर 16 में पहले कहां पर रहते थे, जब उन्हें बताया गया कि उनके घर के पास में ही रहते थे। तब उनका कहना था कि बीएलओ का कहना है कि उनका नाम तो वार्ड नंबर 16 के मतदाता सूची से कट गया है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह क्षत्री द्वारा उन्हें बताया गया कि इतने सालों तक तो उनका नाम वार्ड नंबर 16 की मतदाता सूची में था और अब तक हुए सभी चुनावों में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते आए हैं। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना वोट डाला है, उसके बाद सबसे अंत में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, उसके बाद तो कोई चुनाव नहीं हुआ है, अब कलेक्टर को मैसेज करने के बाद उनका नाम बीएलओ ने काट दिया हो वह अलग बात है। इस पर उज्जवल तिवारी ने उनसे इपिक नंबर मांगा, इपिक नंबर लेने के बाद उनकी ओर से फिर संपर्क नहीं किया गया।

जब एक-दो साल पहले आने वाले अधिकारी जिले के मतदाता तो मैं क्यों नहीं .... ?

मामले के संबंध में राजेश सिंह क्षत्री कहते हैं कि हमारे देश का संविधान 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है, एसआईआर के बाद भी एक दो साल पहले जिले में आने वाले कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार आदि सभी जिले के मतदाता रहेंगे तो मैं क्यों मताधिकार से वंचित रहूंगा, जबकि मेरा पूरा जीवन ही यहीं बीत गया, 2003 की मतदाता सूची में भी यहीं मेरा नाम दर्ज है। वार्ड नं. 16 का बीएलओ इस वार्ड में ये नहीं रहते कहकर नाम काट देगा, वार्ड नं. 08 का बीएलओ अपने पास मौजूद मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है कहकर गणना पत्रक नहीं देगा, जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में मामला लाए जाने के बाद भी जवाबदारों के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी तब तो एसआईआर मेरा मताधिकार ही छिन लेगा।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जांजगीर एवं पेण्ड्री में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का किया निरीक्षण

कम प्रगति वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने विधानसभा जांजगीर-चांपा अंतर्गत जांजगीर एवं पेण्ड्री में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से घर-घर जाकर किए जा रहे सत्यापन, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन और फॉर्म प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बीएलओ अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने कहा कि घर-घर सर्वे के दौरान प्राप्त फॉर्म-6 (नाम जोड़ने), फॉर्म-8 (संशोधन) आदि सभी आवेदन को व्यवस्थित रूप से संकलित कर समय पर जमा किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रगति कम वाले क्षेत्रों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण और पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ की प्रशंसा की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री पवन कोसमा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध धान के भंडारण, परिवहन, विक्रय पर जिला प्रशासन सख्त

पाली के निरधी में 20 क्विंटल अवैध धान जब्त, प्रशासन ने की कार्रवाई

कोरबा (आरएनएस)। खरीफवर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुसार समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान उपार्जन कार्य तेजी से जारी है। इसी के साथ अवैध धान विक्रय और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

खास खबर

एसडीजी डेषबोर्ड डाटा एंट्री किये जाने के निर्देष

कोरबा। कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों- वनमंडलाधिकारी वनमण्डल कोरबा, कटघोरा, उपसंचालक कृषि, समाज कल्याण, अधीक्षक भू-अभिलेख, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, जिला षिक्षा अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रषासन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबबंधन, सहायक श्रमायुक्त, कार्यपालन अभियंता विद्युत, केडा और कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, मध्यम सिंचाई कोरबा को पत्र जारी कर ''एसडीजी डेषबोर्ड में वर्ष 2024-25 डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर की जानकारी एक सप्ताह में एण्ट्री कार्य पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय कोरबा को एक प्रति भेजकर सूचित करना सुनिष्चित करने के निर्देष दिया गया है।

सीएसईबी के मिनी हाइडल प्लांट में घुसा पानी, उत्पादन ठप्प, कर्मचारियों में हड़कंप

कोरबा विद्युत मंडल के एचटीपीएस संयंत्र के पास स्थापित 85 किलोवॉट के मिनी हाइडल प्लांट में आज गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

बताया गया है कि स्टॉप डैम में अचानक दरार आने के कारण बड़ी मात्रा में पानी सीधे प्लांट के भीतर घुस गया। पानी प्लांट में तेजी से भरता देख, भीतर काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पानी भरने के कारण मिनी हाइडल प्लांट में विद्युत उत्पादन पूरी तरह ठप्प हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया। प्लांट में घुसे पानी को निकालने और दरार की मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है।

सुरेश सिंह बैस राष्ट्रीय साहित्य क्रांति प्रोत्साहन परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी के वरिष्ठ साहित्यकार कवि लेखक एवं पत्रकार सुरेश सिंह बैस को साहित्य क्रांति प्रोत्साहन परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त गया है। तत्संबंधित नियुक्ति पत्र प्रेषित करते हुए, राष्ट्रीय विचारक्रांति साहित्य संस्थान सिंगरौली, मध्यप्रदेश के संस्थापक डॉ राजकुमार जायसवाल ने कहां बैस को साहित्यिक गतिविधियों व समाज हित हेतु राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए विचार क्रांति साहित्य प्रोत्साहन परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र में उन्होंने बैस को राष्ट्रीय विचार क्रांति प्रोत्साहन परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद नियुक्ति पश्चात शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सम्माननीय ङ्क सुरेश सिंह बैस शाश्वत जी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ आपको भारत सरकार द्वारा पंजीकृत विचारक्रांति प्रोत्साहन परिषद् में अवैतनिक रूप से समाजहित में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने व परिषद् के कार्यों में तेजी से वृद्धि लाने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षके पद पर नियुक्त किया जाता है।

धान खरीदी के लिए समितियों में प्रभारी अधिकारी नामांकित का संषोधित आदेष जारी

संवाददाता

कोरबा खरीफविपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं वित्तीय प्रषासकीय प्रबंधन का कार्य संयुक्त रूप से समिति प्रबंधक के साथ शासकीय विभागों के अधिकारियों को समिति स्तर पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी हेतु प्रभारी अधिकारी नामांकित किये जाने के जारी पूर्व आदेष को संषोधित किया गया है।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी संषोधित आदेष के अनुसार विकासखंड कटघोरा अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अखरापाली हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुकेष कुमार लहरे, कटघोरा-खाद्य निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार लांझी, छुरीकला-सहकारिता निरीक्षक सुस्मिता लकड़ा, जवाली-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मीनाक्षी ठाकुर, दूरपा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धनेष्वर प्रसाद लहरे और समिति भिलाईबाजार हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रामलाल रविन्द्र को प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।

इसी तरह विकासखंड करतला अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कनकी हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संजय कुमार सोनवानी, करतला-एसएडीओ अजय कंवर, कोथारी-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनिल साण्डे, चिकनीपाली - ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कामता प्रसाद साहू, तुमान-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संजू कुमार पाटले, नवापारा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गजेन्द्र सिंह कंवर, पठिया पाली-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रजनीष सिंह, फरसवानी-खाद्य निरीक्षक पारण सोलंकी, बरपाली (बरपाली)-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजकुमार ताड़िया, रामपुर-सहकारिता निरीक्षक एल.एन. जायसवाल, सुखरीकला - सहकारिता निरीक्षक जी.आर.भतरा और समिति सोहागपुर हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नरेन्द्र कुमार देवांगन को प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।

विकासखंड कोरबा अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोरकोमा हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी सुभद्रा सिदार, तिलकेजा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृष्णा कंवर, बरपाली (कोरबा)-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मोहम्मद सज्जाद, भैंसमा-खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता, श्यांग-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भूपेन्द्र मैत्री और समिति सोनपुरी हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुजाता मुंगेल को प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।

विकासखंड पाली अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उतरदा हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रघुनंदन सिंह कंवर, कोरबी-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजेन्द्र कुमार साहू, चैतमा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रविन्द्र सिंह, निरधि-सहकारिता निरीक्षक भूपेन्द्र साहू, पाली-खाद्य निरीक्षक रवि कुमार राज, पोंड़ी-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बी.एल.पैकरा, लाफा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एच.सी. सेन्द्रे और समिति हरदी बाजार हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुमित कुमार लहरे को प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है। विकासखंड पोंड़ी उपरोड़ा अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कुल्हरिया हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नमस्कार नवरंग, कोरबी-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रामकुमार नेटी, जटगा -वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक दीपक कंवर, पसान-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिपांषु गुप्ता, पिपरिया-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनोज कुमार कंवर, पोंड़ीउपरोड़ा-सहायक खाद्य निरीक्षक सरोज उरेती, बिंझरा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निषांक कुमार कलेष, मोरगा-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राकेष कुमार यादव और समिति सिरमिना हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनीष कुमार डिक्सेना को प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।

आखिर पहुंची उम्मीद की रोशनी

पतुरियाडाँड़ हाई स्कूल में अंग्रेजी व्याख्याता मिलने से छात्रों के सपनों को मिली नई उड़ान

कोरबा (संवाददाता)।

पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे छोटे से गाँव पतुरियाडाँड़ के लिए हाई स्कूल खुलना किसी वरदान से कम नहीं था। वर्षों तक आसपास के गांवों के बच्चे सिर्फ इसलिए आगे की पढ़ाई से वंचित हो जाते थे क्योंकि हाई स्कूल की दूरी अधिक थी। लेकिन जब गाँव में हाई स्कूल प्रारंभ हुआ, तो यह न सिर्फ गांववासियों के लिए खुशी का क्षण था, बल्कि उन बच्चों के लिए नई उम्मीद थी जो उच्च शिक्षा का सपना मन में लिए बैठे थे।

हाई स्कूल खुलने के बावजूद छात्रों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि अंग्रेजी विषय का नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं था। गांव के अधिकांश बच्चे अंग्रेजी और गणित को कठिन विषय मानते थे। अंग्रेजी शिक्षक न होने के कारण खासकर छात्राओं के सपनों पर असर पड़ने लगा था, क्योंकि इस स्कूल में उच्च शिक्षा का सपना देखने वाली अधिकांश विद्यार्थी लड़कियां ही थीं। सरकार की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया इस विद्यालय के लिए किसी सौभाग्य की तरह साबित हुई। इसी प्रक्रिया के तहत यहाँ अंग्रेजी विषय के व्याख्याता विजय कुमार राठौर की नियुक्ति हुई। व्याख्याता के रूप में उन्होंने चार-पांच महीने पहले ज्वाइनिंग दी और तभी से छात्रों के लिए अंग्रेजी का डर धीरे-धीरे कम होता गया।

तत्काल न्याय की पहल, 13 दिसम्बर को समझौते से समाधान का सूत्र, निपटेंगे हजारों प्रकरण

तैयारी हेतु बैठक आयोजित

कोरबा) छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार आगामी 13 दिसम्बर-2025 को जिला एवं तालुका स्तर पर चैथी एवं वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसकी तैयारी के संबंध में 18 नवंबर को श्री संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण की बैठक ली गयी उक्त बैठक बाह्य न्यायालय कटघोरा, करतला, पाली के न्यायाधीशगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम बैठक में भाग लिये। उक्त बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त न्यायाधीशगण से न्यायालयों में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीष ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि उक्त आयोजित लोक अदालत जन सामान्य को त्वरित सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिष्चित करने का आग्रह किया गया है ताकि विवादों को आपसी समझौते से समयबद्ध समाधान किया जा सके। लोक अदालत का उद्देष्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना, लम्बे समय से लंबित प्रकरणों को समाप्त करना और न्याय पालिका पर बोझ घटाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने अधिकतम लाभ हेतु आम जनता से अपील की है कि वे लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर तेज परदर्षी और सौहार्द्र पूर्ण न्याय का लाभ उठाये।

उन्होनें बताया कि समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, लोक अदालत की प्रक्रिया बिलकुल सांक्षिप्त और साधारण है जिसमें दोनो पक्षों की सहमति से प्रकरण का निपटारा किया जाता है दोनो पक्षों की सहमति से प्रकरण का फैसला होने के कारण पक्ष-विपक्ष में वैमनष्यता, मन-मुटाव हमेषा के लिए समाप्त हो जाता है लोग पुनः सामाजिक जीवन जीने लगते हैं।

तत्काल न्याय की पहल, 13 दिसम्बर को समझौते से समाधान का सूत्र, निपटेंगे हजारों प्रकरण

० तैयारी हेतु बैठक आयोजित

कोरबा । छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार आगामी 13 दिसम्बर-2025 को जिला एवं तालुका स्तर पर चैथी एवं वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसकी तैयारी के संबंध में 18 नवंबर को श्री संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण की बैठक ली गयी उक्त बैठक बाह्य न्यायालय कटघोरा, करतला, पाली के न्यायाधीशगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम बैठक में भाग लिये। उक्त बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त न्यायाधीशगण से न्यायालयों में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीष ने अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि उक्त आयोजित लोक अदालत जन सामान्य को त्वरित सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिष्चित करने का आग्रह किया गया है ताकि विवादों को आपसी समझौते से समयबद्ध समाधान किया जा सके।

रिटायर्ड कर्मचारी के घर चोरी, AC का कॉपर तार चुरा ले गए शातिर

बिलासपुर (संवाददाता)।

सरकंडा क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों ने विजयापुरम कालोनी के कई घरों के एसी के केबल, ट्रांसफार्मर के केबलों को चोरी कर लिया है। चोरी से परेशान कालोनी रहवासी सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार विजयापुरम कालोनी निवासी मोहम्मद खालिद हनीफी पिता स्व मोहम्मद ईस्माईल हनीफी एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी है। 16 नवंबर को खाना खाकर सो गए। सुबह उठने पर उन्हें पता चला कि घर में लगे 2 एसी के नट बोल्ट खुले हैं और कॉपर तार चोरी कर लिया गया है।

इस दौरान पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी की जांच करने पर पता चला कि अज्ञात चोर सुबह 4 बजे चोरी जा रहा है। इस तरह 19 नवंबर को दोबारा कालोनी में एसी कॉपर तार की चोरी की गई और पड़ोसी के कैमरे के केबल व ट्रांसफार्मर के कर तार को भी काट कर चोरों ने चोरी कर लिया है। चोरों के आंतक से परेशान होकर रहवासियों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है।

पतुरियाडाँड़ हाई स्कूल में अंग्रेजी व्याख्याता मिलने से छात्रों के सपनों को मिली नई उड़ान

कोरबा (संवाददाता)।

पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे छोटे से गाँव पतुरियाडाँड़ के लिए हाई स्कूल खुलना किसी वरदान से कम नहीं था। वर्षों तक आसपास के गांवों के बच्चे सिर्फइसलिए आगे की पढ़ाई से वंचित हो जाते थे क्योंकि हाई स्कूल की दूरी अधिक थी। लेकिन जब गाँव में हाई स्कूल प्रारंभ हुआ, तो यह न सिर्फगांववासियों के लिए खुशी का क्षण था, बल्कि उन बच्चों के लिए नई उम्मीद थी जो उच्च शिक्षा का सपना मन में लिए बैठे थे।

हाई स्कूल खुलने के बावजूद छात्रों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि अंग्रेजी विषय का नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं था। गांव के अधिकांश बच्चे अंग्रेजी और गणित को कठिन विषय मानते थे। अंग्रेजी शिक्षक न होने के कारण खासकर छात्राओं के सपनों पर असर पड़ने लगा था, क्योंकि इस स्कूल में उच्च शिक्षा का सपना देखने वाली अधिकांश विद्यार्थी लड़कियां ही थीं। सरकार की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया इस विद्यालय के लिए किसी सौभाग्य की तरह साबित हुई। इसी प्रक्रिया के तहत यहाँ अंग्रेजी विषय के व्याख्याता विजय कुमार राठौर की नियुक्ति हुई। व्याख्याता के रूप में उन्होंने चार-पांच महीने पहले ज्वाइनिंग दी और तभी से छात्रों के लिए अंग्रेजी का डर धीरे-धीरे कम होता गया।

अब बच्चे बताते हैं कि ÷सर के आने के बाद अंग्रेजी पढ़ना मुश्किल नहीं लगता। अब हमें समझ में भी आता है और नियमित क्लास भी होती है।÷ कक्षा 9वीं की छात्राएँ कुमार धन कुंवर, सुनती, सरिता, सपना, विक्रम और 10वीं के विद्यार्थी आकांक्षा, अमृता, राजकुमारी, विजय, विष्णु, अशोक सभी एक ही बात कहते हैं ÷अगर शिक्षक नहीं होते तो हम कठिन विषय में फेल भी हो सकते थे। अब हमें अपने भविष्य पर भरोसा है।÷ गांव के लोगों के चेहरे पर भी खुशी झलकती है। वर्षों से जिस योग्य शिक्षक की कमी महसूस होती थी, वह अब पूरी हो गई है। आज गांव के बच्चे अंग्रेजी में मजबूत हो रहे हैं, परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आत्मविश्वास से भर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति ने पतुरियाडाँड़ के इस विद्यालय का भविष्य ही नहीं बदला है, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में नई रोशनी भरी है, जो कल अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।

36.74 करोड़ की जल प्रदाय योजना विस्तार से कोरबा में जल आपूर्ति तंत्र होगा सुदृढ़

कोरबा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में जिले में पेयजल सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला खनिज संस्थान न्यास के अध्यक्ष अजीत बसंत ने नगर निगम कोरबा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए 36.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

जल प्रदाय व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा

इस स्वीकृति के बाद शहर में जल आपूर्ति तंत्र के उन्नयन, नई पाइपलाइन बिछाने, जल स्रोतों के विकास तथा आधुनिक तकनीक आधारित वितरण प्रणाली के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नगर निगम क्षेत्र के हजारों परिवारों को सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध होगा। जल प्रदाय योजना विस्तार के अंतर्गत कोरबा में 20 एमएलडी क्षमता वाले जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 30 बीएचपी के क्लीयर वॉटर पंप मशीनरी के 03 सेट, क्लीयर वॉटर पम्पिंग मेन पाइपलाइन (300-200 मिमी व्यास, 4680 मीटर), क्लीयर वॉटर ग्रैविटी मेन पाइपलाइन (500-200 मिमी व्यास, 10,470 मीटर) एवं 03 उच्च जलागार रुगमरा दृ (1080 केएल) इमलीडूग्गू (1260 केएल) व दादर (2250 केएल) का निर्माण कार्य किया जाएगा।

योजना पूर्ण होने पर कोरबा नगरीय क्षेत्र के मोतीसागर पारा, ईमलीडूग्गू, भिलाई खुर्द, दादर खुर्द, मानिकपुर, खरमोरा, पीएम आवास दादर, बेलगीरी बस्ती, रुमगरा, कोहडिया एवं प्रगतिनगर सहित विभिन्न वार्डों के लगभग 57,740 नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

जिला प्रशासन का यह निर्णय कोरबा शहर में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे आने वाले समय में जनस्वास्थ्य एवं नगरीय सुविधाओं के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

राजभवन में मनाया गया 6 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान पर उन्मुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न

सुकमा छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में बाल विवाह की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियानकी शुरुआत की गई। अभियान का प्रमुख लक्ष्य बाल विवाह पर पूर्ण रोक लगाते हुए राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इसी क्रम में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव एवं सीईओ जिला पंचायत मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना के तहत शुक्रवार को जनपद पंचायत कोंटा के सभाकक्ष में प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गयाकार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल संरक्षण की विभिन्न व्यवस्थाओं, विधि से संघर्षरत बालक, पॉक्सो, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, चाइल्ड हेल्पलाइन, स्पॉन्सरशिप, दत्तक ग्रहण एवं पलायन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई।कार्यक्रम में जनपद पंचायत कोंटा की अध्यक्ष कुसुमलता कवासी, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोंटा सुमित ध्रुव, परियोजना अधिकारी कोंटा उत्तम प्रसाद, जिला बाल संरक्षण अधिकारी जितेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य जगत के प्रतिष्ठित 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य की उस विराट परंपरा के प्रतिनिधि हैं, जिसने अपनी सादगी, संवेदना और अद्भुत लेखन-शक्ति से साहित्य की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उनकी लेखनी ने न केवल हिंदी भाषा को समृद्ध किया है, बल्कि पाठकों की अनेक पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि विनोद कुमार शुक्ल को यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान साहित्य जगत में उनके अद्वितीय योगदान को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री विनोद कुमार शुक्ल के सुदीर्घ, स्वस्थ और सक्रिय जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनका रचनात्मक योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष पर चार सदस्यों ने लगाया पद दुरुपयोग और शासकीय प्रक्रिया उल्लंघन का आरोप

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के खिलाफ आयोग की चार सदस्याओं–लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका सोरी–ने शुक्रवार को मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को भेजी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष द्वारा आयोग अधिनियम और शासकीय प्रक्रिया के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कलेक्टर और एसपी सहित विभिन्न अधिकारियों को सीधे पत्र भेजे जा रहे हैं।

शिकायत में सदस्यों ने उल्लेख किया है कि राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 5 और प्रक्रिया विनियम 1998 की कंडिका 13 के अनुसार आयोग से जारी होने वाले आदेश व निर्णय सचिव या फिर अवर सचिव से ऊपर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने अनिवार्य हैं। सदस्यों का कहना है कि आयोग के पास नियमित सचिवालय मौजूद होने के बावजूद अध्यक्ष स्वयं फाइल संचालन, पत्राचार और बैठक संबंधी सूचनाएं जारी कर रही हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है। सदस्यों ने राज्य शासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि आयोग का संचालन नियमानुसार न होकर मनमाने तरीके से किया जा रहा है। उनका कहना है कि सामान्य प्रशासनिक प्रणाली को नजरअंदाज करते हुए अध्यक्ष सीधे जिला अधिकारियों को पत्र भेज रही हैं, जो पद के दुरुपयोग और कार्यालयीन प्रक्रियाओं के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

प्रशासन की तत्परता– दोरनापाल नगर पंचायत की निविदा प्रक्रिया की होगी गहन जांच

सुकमा, जिला प्रशासन ने विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर पंचायत दोरनापाल की जारी निविदा प्रक्रिया की विस्तृत जांच के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने संबंधित प्रक्रियाओं की नियमानुसार समीक्षा हेतु एसडीएम कोन्टा सुभाष शुक्ला और जनपद सीईओ कोन्टा सुमित कुमार ध्रुव को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

छत्तीसगढ़ के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का पहुँचे लाभ - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक संपन्न

जनकल्याणकारी योजनाओं का तेज़ और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की व्यापक और विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे तथा सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दिशा समिति की बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं बैठकों के माध्यम से केंद्र पोषित योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक 6 माह में दिशा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। उन्होंने बताया कि 26 विभागों के अंतर्गत कुल 81 योजनाएँ संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वे जिले स्तर पर आयोजित प्रत्येक तिमाही दिशा समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक की नियमितता, बेहतर समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह समिति विकास कार्यों की दिशा तय करने वाली प्रमुख संस्था है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित पीएम जनमन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्थिति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए और किसी भी पात्र किसान को लाभ से वंचित न रखा जाए। उन्होंने इस दौरान वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की स्थिति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रारम्भ हुई डेयरी समग्र विकास योजना की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के साथ-साथ पारंपरिक रूप से दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को भी योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि योजना को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मिशन अमृत, तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शहरी आवास निर्माण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जारी आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन कार्ड की संख्या पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने नियद नेल्ला नार क्षेत्र के गांवों में विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने और हितग्राहियों की सुविधा के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं पोषण योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मध्याह्न भोजन की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ प्रदेश के विकास का आधार हैं। उन्होंने 'न्योता भोज' पहल की निरंतरता की जानकारी ली और जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने टेलिकॉम सेक्टर में भारत नेट परियोजना की प्रगति धीमी होने पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने फाइबर नेटवर्क का कार्य शीघ्र पूर्ण करने और बस्तर एवं सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी भी ली गई। बैठक में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुकेश बंसल, बसव राजू एस. सहित विभागों के भारसाधक सचिव एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

रायपुर, रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के प्रभाव को रोकने के लिए की गई है।

कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 21 नवंबर 2025 के अनुसार यह निर्देश दिया है कि यह तीनों अपराधी आदेश की तिथि से 7 दिवस यानी 27 नवंबर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर रहें। इसके बाद भी तीन माह तक यानी 20 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तीनों अपराधियों में पहला है राहुल सेन, पिता संतोष मनसाना, उम्र 29 वर्ष, निवासी तिल्दा बस्ती, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर। राहुल के विरुद्ध चैन स्नेचिंग, चोरी और नकबजनी जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। दूसरा अपराधी चंदन जैन, पिता कोमल जैन, उम्र 26 वर्ष, निवासी लर्रापारा नवापारा, थाना गोबरानवापारा, जिला रायपुर। चंदन के विरुद्ध बलवा, अवैध शराब बिक्री, मारपीट, गुण्डागर्दी और जुआ खेलने जैसे अपराध दर्ज हैं।

नवाचार की नई मिसाल- हरसिंह ओयामी का एकीकृत खेती मॉडल बना प्रेरणा

दंतेवाड़ा, । ग्राम बिंजाम, विकासखंड गीदम के 57 वर्षीय प्रगतिशील किसान हरसिंह ओयामी आज जिले में जैविक खेती के प्रेरणास्रोत के रूप में उभरकर सामने आए हैं। परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी पूरी कृषि प्रणाली को जैविक, टिकाऊ और लाभदायक मॉडल में परिवर्तित किया है। परिवार के सहयोग, सतत प्रयास और वैज्ञानिक सोच ने उन्हें जिले के अग्रणी जैविक किसानों में शामिल कर दिया है।उल्लेखनीय है कि हरसिंग ओयामी को कृषि विभाग के मार्गदर्शन में पक्का पशु शेड, नाडेप टांका, वर्मी टांका और अन्य जैविक संरचनाओं का लाभ मिला। इसके अलावा देशी गायों के सुव्यवस्थित पशुपालन ने उनकी जैविक खेती को मजबूत आधार प्रदान किया। हरसिंग ओयामी जैविक कृषि में इतने प्रवीण हो गए है कि अपने खेत में वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे देशी जैविक कीटनाशक व उर्वरक स्वयं तैयार करते हैं। इससे न केवल कृषि लागत में कमी आई,बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के साथ-साथ फसलें अधिक गुणवत्तापूर्ण बनीं।उनके कृषि क्षेत्र एवं कृषि पैदावार को को देखना एक सुखद अनुभव देता है। उनकी खेती की सबसे बड़ी विषेषता फसल विविधता है। वे विधि, लाइन विधि और पारंपरिक विधि से देशी धान का उत्पादन करते हैं। साथ ही बैंगन, टमाटर, गोभी, मटर, मूली, गाजर, लाल भाजी, मेथी, दलहन, तिलहन सहित अनेक सब्जियों एवं फसलों की वर्षभर खेती करते हैं। इसके अलावा मिलेटस के तहत रागी, कोदो-कुटकी, का उत्पादन, बागवानी के तहत आम, अमरूद और वाटर एप्पल जैसे फलों की खेती ने उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस तरह उनके जैविक उत्पादों की बढ़ती बाजार मांग ने उन्हें अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा किया है।हरसिंह ओयामी ने न केवल कृषि बल्कि मत्स्य उत्पादन में भी बढ़त हासिल कर चुके है। एग्री-फिशरी मॉडल अपनाकर उन्होंने आय के नए स्रोत बनाए। उन्हें डबरी एवं ओरनामेंटल फिश पद्धति से मत्स्य उत्पादन कर लगभग 1,00,000 रूपये वार्षिक शुद्ध आय अर्जित किया है। जहां डबरी का पोषक जल उनकी जैविक खेती में अमृत समान सिद्ध हुआ। वहीं उनका फसल उत्पादन बढ़ा, कीटनाशक की आवश्यकता घटी और मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार बेहतर हुआ।आज उनकी जैविक खेती, फसल विविधता, पशुपालन और मछली पालन का एकीकृत मॉडल उन्हें लगभग 7,00,000 रूपये की वार्षिक आय प्रदान कर रहा है। उनका खेत अब केवल उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि सीखने और प्रेरणा का मॉडल फार्म बन चुका है, जहाँ अन्य किसान जैविक कृषि और मत्स्य पालन की नई तकनीकें सीखने आते हैं। श्री हरसिंह ओयामी ने सिद्ध कर दिया है कि जैविक खेती न केवल परंपरा, बल्कि भविष्य की सतत व समृद्ध कृषि का मजबूत स्तंभ है। स्थानीय संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, मेहनत और नवाचार उन्हें दंतेवाड़ा के किसानों के लिए प्रेरणा का पथप्रदर्शक बनाते हैं।

शीत लहर से निपटने के लिए जनहित में दिशा-निर्देश जारी

विद्यालय में शिक्षकों के विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ

नगरी, 19 नवम्बर को संयुक्त रूप से संकुल केन्द्र चारगांव एवं भैसामुड़ा के समस्त शिक्षकों, पालकों एवं ग्रामीणों की सहभागिता से स्वागत सम्मान व विदाई समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रकाश चंद साहू (वि.खं. स्त्रोत समन्वयक) नगरी, अध्यक्षता श्री घनश्याम सिन्हा (व्याख्याता) हाई स्कूल भैसामुड़ा एवं विशिष्ट अतिथि कौशिल्या मरकाम(सरपंच) ग्रा.पं. जबर्रा, श्री लखन मंडावी (उपसरपंच) ग्रा.पं. भैसामुड़ा एवं दोनों पंचायत के प्रभुद्ध जन के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।

शासकीय माध्यमिक विद्यालय चारगांव में शिक्षकों, अभिभावकों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में युक्?ति-युक्तकरण से नव नियुक्त शिक्षक सरोज कुमार नेताम (सहा.शि.) प्राथ. शाला चारगांव, टिकेश्वर साहू (सहा. शि.) प्राथ. शाला तुमबाहरा शिक्षकों का भव्य स्वागत, नवीन प्रधान पाठक श्री अमृत लाल साहू (प्र.पा.) माध्य.शाला. चारगांव, श्री नंदकिशोर ध्रुव (प्र.पा.) माध्य.शाला. भैसामुड़ा एवं श्री किशोर कुमार नवरंग (प्र.पा.) माध्य.शाला खुदुरपानी का सम्मान, तथा एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित निशित सोम(सहा. शि.) प्राथ. शाला मटियाबाहरा एवं श्री सरस कुमार साहू सेवा निवृत्त शिक्षक (से.नि. प्र.पा.) माध्य.शाला. चारगांव का विदाई समारोह गरिमामय रूप से आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलन एवं स्वागत गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। इसके पश्चात् विद्यालय परिवार, पालकगण और ग्रामीणजनों ने नव नियुक्त शिक्षकों का श्रीफल शाल-श्रृंगार व प्रतीक चिन्ह से स्वागत सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में हाल ही में पदस्थ हुए नवीन प्रधान पाठक का विशेष सम्मान किया गया। शिक्षकों एवं ग्रामीणों ने विद्यालय के शैक्षिक वातावरण और अनुशासन को मजबूत करने में उनके योगदान की अपेक्षा व्यक्त की। इसके बाद एक अन्य संस्था में स्थानांतरित होकर गए शिक्षक तथा सेवा निवृत्त हुए शिक्षक को भावपूर्ण सम्मान व विदाई दी गई। उनके योगदान, सेवाभाव और विद्यार्थियों को दी गई मूल्यवान शिक्षा को सभी ने स्मरण किया। विदाई के उदबोधन से शिक्षकों व पालकों ने अपने अनुभव भी साझा किए, जिससे वातावरण भावुक हो उठा।

ऑनलाइन टोकन से बढ़ी सुविधा, धान विक्रय में मिली गति - किसान टीकाराम साहू बने तकनीक-सक्षम प्रगतिशील किसान

धमतरी, जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था इस वर्ष और अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित तथा किसान हितैषी सिद्ध हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा तकनीकी नवाचारों और सुगम सेवाओं के विस्तार के साथ किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बेहतर परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में कुरूद विकासखंड के ग्राम गातापार के प्रगतिशील किसान टीकाराम साहू की सफलता की कहानी पूरे जिले के किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है। साहू ने सेवा सहकारी समिति कोड़ेबोड में पहुंचकर 144 क्विंटल धान की बिक्री की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष खरीदी व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव वे महसूस कर रहे हैं, वह है 'टोकन तुम्हार द्वार' मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा। इस डिजिटल नवाचार ने किसानों को भारी भीड़, लंबी कतारों और अनावश्यक समय व्यय से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। टीकाराम ने आसानी से ऑनलाइन टोकन बुक किया और निर्धारित समय पर खरीदी केंद्र पहुंचकर सुचारू रूप से अपना धान विक्रय किया। टीकाराम ने इस वर्ष 4 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती की है। समय पर सिंचाई, उन्नत कृषि पद्धतियों तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से उन्हें बेहतर उत्पादन प्राप्त हुआ। वे बताते हैं कि गत वर्ष खरीदे गए जॉन डियर ट्रैक्टर ने खेती-किसानी के कार्यों में उनकी मेहनत कम की और उत्पादन क्षमता में वृद्धि की। खेत की जुताई, समतलीकरण और कटाई-परिवहन जैसे कार्य अब पहले की तुलना में अधिक तेजी और कम लागत में हो रहे हैं। धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे कृषि ऋण के भुगतान, अगली फसल के लिए खाद-बीज की खरीदी तथा खेती के अन्य आवश्यक कार्यों में करेंगे। इसके अतिरिक्त, साहू अपने दो बेटों का विवाह इसी वर्ष करने की तैयारी में हैं। इस शुभ अवसर पर वे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भी निमंत्रण देने की बात भावनात्मक उत्साह के साथ बताते हैं। टीकाराम साहू का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई सुविधाएँ–चाहे वह ऑनलाइन टोकन व्यवस्था हो, खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्थाएँ हों या किसानों के लिए कृषि साधन उपलब्ध कराने के प्रयास–किसानों की दैनिक समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बना रही हैं। धमतरी जिले में आधुनिक तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के संगम से उभर रहे नये ग्रामीण विकास का जीवंत उदाहरण है– जहाँ किसान आत्मनिर्भरता की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ा रहे हैं।

कलेक्टर दुदावत का दूरस्थ ग्रामों का दौरा एसआईआर गणना कार्य में तेजी के निर्देश

दंतेवाड़ा, कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के ग्राम मेटनार, पोन्दुम, मेटापाल और दूरस्थ ग्राम तुमकपाल का दौरा कर वहां चल रहे एसआईआर (सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचा रजिस्ट्री) गणना कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने गणना पत्रक वितरण, संधारण और सर्वेक्षण प्रक्रिया का विस्तार से अवलोकन करते हुए बीएलओ और सुपरवाइजरों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एसआईआर गणना जिले के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। अतः गणना पत्रक भरने के कार्य में दूरस्थ ग्रामों में इस संबंध में कुछ दिक्कतें आ सकती है। परन्तु निराकरण भी करना भी हमारा प्रमुख दायित्व है। ग्रामीणजनों को स्पष्ट रूप से समझाए कि गहन पुनरीक्षण कार्य उनके भावी पीढ़ी की सुविधाजनक जीवन के लिए अनिवार्य है। यहां अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि गणनाकर्मियों को समय पर पत्रक उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे सर्वेक्षण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके। कलेक्टर ने फील्ड सत्यापन को अनिवार्य बताते हुए कहा कि प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता ही भविष्य की योजनाओं की मजबूती का आधार होगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामवार स्थिति की जानकारी ली। इस संबंध में बीएलओ द्वारा जानकारी दी गई कि मटेनार में 1048 में से सभी पत्रक वितरित कर दिए गए हैं और भरे हुए 150 पत्रक जमा हो चुके हैं। इस क्रम में ग्राम पोन्दुम में 662 पत्रकों में से 600, मेटापाल में 903 में से 150 पत्रक, जबकि तुमकपाल में 1077 पत्रक वितरित हुए जिनमें से 411 जमा हो चुके हैं।कलेक्टर दुदावत ने ग्रामीणों से भी संवाद कर उन्हें गणना पत्रक को ध्यानपूर्वक भरने, पावती लेने और सही जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)